

**बजट
2021-22**

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया. बजट में कृषि क्षेत्र को खास अहमियत दी गयी है. नये कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को इसके जरिये संदेश देने की कोशिश की गयी है. इस साल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं. सरकार इन राज्यों पर बजट में मेहरबान दिखी.



**विकास
पर खर्च**

5.54

लाख करोड़ रुपये बजट में पूंजीगत खर्च, यानी विकास कार्यों पर खर्च के लिए रखे गये हैं.

खर्च के लिए कर्ज

12 लाख करोड़ रुपये कर्ज

से जुटायेगी सरकार, जो सरकार की कुल आमदनी का 36 फीसदी होगा. बाकी पैसे टैक्स व लाभांश से आयेगे.

**राजकोषीय
घाटे का हाल**

राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में जीडीपी के 9.5 फीसदी तक पहुंच सकता है. नये वित्त वर्ष में इसके 6.8 फीसदी रहने का अनुमान.

अर्थव्यवस्था को उम्मीदों की वैक्सीन

1 कई उत्पादों पर आधी रात से लागू हुआ कृषि बुनियादी ढांचा सेस

2 पेट्रोल पर 2.5 व डीजल पर चार रुपये लीटर सेस, पर अभी बोझ नहीं

3 75 साल से ऊपर के पेंशनभोगियों को रिटर्न से छूट, आयकर से नहीं

4 तीन साल पहले तक के ही आयकर आकलन मामले खोले जा सकेंगे

5 होम लोन ब्याज पर करयोग्य आय से 1.5 लाख की कटौती रहेगी जारी

महंगा

मोबाइल व चार्जर, एसी और फिज, एलइडी लाइट, सूती कपड़े, गाड़ियों के कल-पुर्जे, स्कू व नट, सोलर इनवर्टर व लैप, कच्चा रेशम, कृत्रिम रत्न, तार व केबल

सस्ता

सोना-चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम, नैपथा, लौह व इस्पात कबाड़, तांबा कबाड़, एमएसएमइ के काम आनेवाले कई इस्पात उत्पाद, विमानों के कल-पुर्जे



बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने और किसानों की आय बढ़ाने पर बहुत जोर दिया गया है. किसानों को आसानी से ज्यादा कर्ज मिल सकेगा. मंडियों को और मजबूत करने का प्रावधान किया गया है.

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



कोरोना महामारी के चलते संकट से गुजर रहे लोगों के हाथों में पैसे देने के बारे में सरकार भूल गयी. मोदी सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है.

राहुल गांधी, कांग्रेस नेता



राजस्थान को केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीदें थीं. लेकिन प्रदेश की जनता को इससे निराशा हुई है. पब्लिक के लिए इस बजट में बुरी खबरें ही हैं. पेट्रोल-डीजल पर नार सेस लगाकर इसकी कीमत में कोई राहत नहीं दी है.

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

**डिजिटल
बजट**

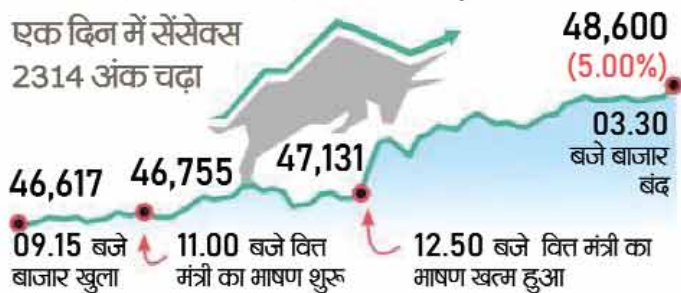
पहली बार पेपरलेस बजट. वित्त मंत्री ने टैबलेट से पहा बजट भाषण. सांसदों को मिली बजट की डिजिटल कॉपी.

जस का तस

आयकर की दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं.

बाजार में रोनाक

24 साल में सबसे बड़ी उछाल



इससे पहले 1977 में बजट के दिन सेंसेक्स छह फीसदी चढ़ा था

सोना सस्ता, पर चांदी महंगी: बजट में सोने-चांदी के आयात शुल्क में कटौती की घोषणा के बाद दिल्ली सरफा बाजार में सोना 1,324 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरा. वहीं, चांदी 3,461 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गयी.



₹2,50,000 वार्षिक से ज्यादा अंशदान है तो पीएफ के ब्याज पर टैक्स

₹50,00,000 से अधिक का माल एक साल में लेने पर बड़े कारोबारियों के लिए 0.1% टीडीएस

सब्सिडी... रसोई गैस पर सब्सिडी का फंड 62% घटाया, लेकिन खाद्य सब्सिडी दोगुनी की

सरकार ने पहली बार केरोसिन पर सब्सिडी खत्म की है। साथ ही एलपीजी पर सब्सिडी 62.2 प्रतिशत घटाई है। लेकिन, खाद्य सब्सिडी 110 प्रतिशत बढ़ा दी गई है। इसका सीधा असर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बंटने वाले मुफ्त या सस्ते राशन पर पड़ेगा। अभी 50 करोड़ से ज्यादा लोग इस प्रणाली से जुड़े हुए हैं। सरकार ने हर उस वस्तु का आयात महंगा किया जो देश में बन सकती है...

सरकार ने लंबे समय बाद कस्टम व एक्साइज ड्यूटी में काफी बदलाव किए हैं। फ्री टैरिफ पर देखा जाए तो इससे मोबाइल, मोबाइल चार्जर, फिज-एसी व साइकिल जैसी चीजें महंगी होती नजर आ रही हैं। अगर बारीकी से देखा जाए तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ाया कदम है। सरकार ने एथाइल एल्कोहल का आयात महंगा किया है। इससे बनने वाले एथेनॉल का इस्तेमाल क्लीन फ्यूल बनाने में करने की कवायद जारी है। पेट्रोल में 22% तक एथेनॉल मिलाया जा सकता है, अभी देश में 10% ही मिलाया जा रहा है। देश में गन्ना, मक्का और धान जैसी फसलों के अवशेष उत्पाद से एथेनॉल बनाया जा सकता

है। ऐसे में इसका आयात महंगा करना घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। सरकार ने कूड पाम ऑयल, कूड सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल का आयात महंगा किया है। इससे घरेलू खाद्य तेल निर्माता कंपनियों को देश की ही उज पर फोकस करना होगा। सरकार ने स्टील-आयर्न स्केप का आयात सस्ता किया है, जबकि स्टेन, नट-बोल्ट का आयात महंगा कर दिया है। यानी कच्चे माल का आयात तो सस्ता होगा, अगर तैयार माल का आयात महंगा होगा। यह कदम चीन की बाजार नीति पर सज्जकल स्ट्राइक जैसा है।

तरित टिप्पणी

आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश

कोरोना संकट ने देश-दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है. यह बजट इस आपदा में अवसर तलाशने की एक कोशिश है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार की उम्मीद जतायी, साथ ही कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत का विजन है. वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट छह स्तंभों पर टिका है. पहला स्तंभ है- स्वास्थ्य, दूसरा- पूंजी और बुनियादी ढांचा, तीसरा- समग्र विकास, पांचवां- नवाचार और अनुसंधान तथा छठा स्तंभ- न्यूनतर सरकार और अधिकतर शासन. जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, कोरोना के महेनजर स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यह बजट ऐसे वक्त में आया है, जब देश की जीडीपी में भारी गिरावट आयी है. सवाल यह है कि क्या यह बजट 2021 में अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने में मददगार साबित होगा? अर्थव्यवस्था की इस सुस्ती से सभी चिंतित हैं. हालांकि इस सुस्ती को सीमित अवधि का बताया जा रहा है. बजट में लोगों की निगाहें इसी पर लगी थीं कि सरकार इस सुस्ती को दूर करने के लिए क्या कदम उठाती है. इसमें सबसे अहम इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश को माना जाता है. इस क्षेत्र में निवेश अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है. देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गयी हैं. लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इन योजनाओं को धरातल पर उतारने की है. इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और चुनावी साल में वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए नेशनल हाइवे और नये इकोनॉमिक कॉरिडोर का एलान किया है. शेर बाजार को यह बजट बेहद पसंद आया और सेंसेक्स में भारी उछाल आयी. पिछले कुछ वर्षों की बजट बाद की यह सबसे बड़ी उछाल है, लेकिन यह भी सच है कि शेर बाजार अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर पेश नहीं करता है. देश में अर्थव्यवस्था सुस्त है, लेकिन पिछले कुछ समय से देश में शेर बाजार नित नये रिकॉर्ड बना रहा है.

**बजट
जागरूक**



जनता व्यू



जागरूक जनता

विश्वसनीय साप्ताहिक अखबार

Digital Edition

एक सकारात्मक सोच

जयपुर, बुधवार 3 फरवरी - 9 फरवरी, 2021

राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में प्रसारित

jagrukjanta.in

/jagrukjanta

/jagrukjantanews

jagruk_janta



बजट 2021-22

पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का एलान, 64180 करोड़ होंगे खर्च

सबकी सेहत का ख्याल ढाई गुना बढ़ा हेल्थ बजट

एजेंसियां नयी दिल्ली

कोरोना वायरस महामारी से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में आम आदमी की सेहत का खास ख्याल रखा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट पेश करते हुए 'पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' का एलान किया. यह योजना छह साल के लिए होगी और इस पर 64,180 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जायेगा. नयी और आनेवाली बीमारियों की पहचान और उनका इलाज करने के लिए नयी संस्थाएं बनायीं जायेंगी. यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी. इसके अलावा, वित्त मंत्री ने 2021-22 के स्वास्थ्य बजट में 137 फीसदी की बढ़ोतरी की है. इसे 94,452 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 2,23,846 करोड़ रुपये किया गया है, जो मौजूदा स्वास्थ्य बजट से करीब ढाई गुना ज्यादा है.

70 हजार ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जायेंगे: वित्त मंत्री ने बजट में 70 हजार ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोलने का एलान किया है. 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर भी खोले जायेंगे. इनके अलावा, 11 राज्यों के सभी जिलों में जांच केंद्र और 3382 ब्लॉक में स्वास्थ्य सेंटर बनाये जायेंगे. 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे. नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंप्रोवमेंट पोर्टल को भी मजबूत किया जायेगा. साथ ही 17 नये पब्लिक हेल्थ यूनिट को भी चालू किया जायेगा. वहीं, 33 मौजूदा पब्लिक हेल्थ यूनिट को मजबूत किया जायेगा.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बननेगा: वित्त मंत्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनाने को भी घोषणा की है. इसके तहत नौ बायो सेफ्टी लेवल-3 लैब बनाये जायेंगे. चार इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी खुलेंगे. **कोरोना से निबटने के लिए अब तक 34.50 लाख करोड़ खर्च:** वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना से संबंधित राहत कदमों के कारण 2020-21 में अब तक 34.50 लाख करोड़ खर्च किये जा चुके हैं, जबकि पिछले साल बजट में 30.42 लाख करोड़ के खर्च का प्रावधान किया गया था.

शहरी स्वच्छता मिशन

1,48,000

करोड़ रुपये पांच साल में किये जायेंगे खर्च



निमोकोकल वैक्सीनशन देशभर में होगा शुरू

वित्त मंत्री ने देशभर में न्यूमोकोकल वैक्सीन उपलब्ध करायें जाने की घोषणा की है. इससे हर साल 50,000 से अधिक बच्चों की जान बचायी जा सकेगी. न्यूमोकोकल वैक्सीन निमोनिया, सेप्टीसीमिया और मेनिन्जाइटिस जैसी घातक बीमारियों के खिलाफ प्रभावी है. स्वदेशी न्यूमोकोकल वैक्सीन अभी केवल पांच राज्यों तक सीमित है.

न्यूट्रिशन पर फोकस

2,700

करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी



अब मिशन पोषण 2.0 किया जायेगा लॉन्च

संगठक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय किया जायेगा. इनके स्थान पर मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जायेगा. 112 जिलों में न्यूट्रिशन कार्यक्रम को मजबूत किया जायेगा.

जल जीवन

50,000

करोड़ से 2.86 करोड़ घरों को मिलेंगे नल कनेक्शन



4378 शहरी निकाश्यों में नल कनेक्शन

जल जीवन मिशन (अर्बन) के लिए 50,000 करोड़ आवंटित हुए हैं. इस मिशन के तहत 4,378 शहरी स्थानीय निकाश्यों को 2.86 करोड़ घरों में नल कनेक्शन दिये जायेंगे.



प्रदूषण से निबटने पर जोर

- 1 वायु प्रदूषण से निबटने के लिए 42 शहरों को 2217 करोड़ रुपये आवंटित
- 2 470 करोड़ रुपये प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिये गये हैं.
- 3 500 अमृत शहरों में सैनिटाइजेशन किया जायेगा
- 4 02 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे हवा को स्वच्छ करने पर
- 5 14,793.66 करोड़ रुपये विज्ञान मंत्रालय को आवंटित किये गये हैं
- 6 1897.13 करोड़ रुपये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को मिले

दिव्यांग होंगे सशक्त

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का बजट 28 फीसदी बढ़ा

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए इस बार के बजट में 11,689.39 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछली बार के मुकाबले 28.35 फीसदी अधिक है. वहीं, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को 1171.77 करोड़ रुपये मिलेंगे.

250 करोड़ रुपये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को मिलेंगे

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए अब 38 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो पहले 20 करोड़ थे

किसको कितना मिला धन

- 71,268.71 करोड़ : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- 2,663.00 करोड़ : स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
- 2,970.30 करोड़ : आयुष मंत्रालय
- 60,030 करोड़ : पंचायत और रक्षकता विभाग
- 9,022.57 करोड़ : जल संचायन विभाग, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग

आदिवासी मंत्रालय को 7524 करोड़

सरकार ने केंद्रीय बजट में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए 7,524 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 36 प्रतिशत ज्यादा है. मंत्रालय को 2020-21 में 7,411 करोड़ रुपये मिले थे, जिसे बाद में इसे 85,508 करोड़ किया गया था.

7,524 करोड़ में से 2,393 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे आदिवासी शिक्षा पर

250 करोड़ रुपये खर्च होंगे विशेष रूप से कला और आदिवासी समूहों के विकास पर

महामारी से सबक
2,23,846 करोड़ रुपये का है स्वास्थ्य बजट, जो पिछले वर्ष 94,452 करोड़ रुपये का था

टीकाकरण
35,000 करोड़ रुपये 2021-22 में कोरोना वैक्सीन पर खर्च किये जायेंगे, गुजरात पड़ी, तो इसे और बढ़ाया जायेगा

602
जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे

04
इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनाये जायेंगे

11
राज्यों के सभी जिलों में जांच केंद्र भी बनाये जायेंगे

15
हेल्थ इनरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स व दो मोबाइल अस्पताल खुलेंगे

पेट्रोलियम व गैस

1,00,00,000

और लाभार्थियों को मिलेगा उज्वला योजना का लाभ

08 करोड़ परिवारों को अब तक मिल चुका है उज्वला योजना का लाभ

03 वर्षों में शहरी गैस वितरण नेटवर्क में 100 अतिरिक्त शहरों को जोड़ा जायेगा

जम्मू-कश्मीर में एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा

जनगणना के लिए 3,726 करोड़ आवंटित


जनगणना पर 3,726 करोड़ खर्च होंगे. पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी. कोरोना के कारण 2021 में जनगणना स्थगित है.

‘एक राइट-एक राशन कार्ड’ के तहत अभी 32 राज्यों के 69 करोड़ लोग लाभान्वित हैं. आनेवाले समय में पूरे देश में इसे लागू किया जायेगा.


प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में सामान्य वाहक क्षमता की बुकिंग और समन्वय के लिए एक स्वतंत्र गैस वाहक प्रणाली की स्थापना की जायेगी.

इवीएम की खरीद के लिए धन आवंटित


इवीएम से जुड़ी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वॉटर वैरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल यूनिट खरीदने तथा पुरानी वोटिंग मशीनों को नष्ट करने पर निवाचन आयोग को धन देने के लिए विधि मंत्रालय को 1,005 करोड़ मिले हैं. मतदाता पहचान पत्रों के लिए 7.20 करोड़ रुपये दिये गये हैं. वहीं, चुनाव आयोग को 249.16 करोड़ मिले हैं.




डॉ. हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री



डॉ. मनोज सिन्हा, राज्य स्वास्थ्य मंत्री



डॉ. पूनम क्षेत्रपाल, क्षेत्रीय निदेशक विकास-पूर्व पश्चिम, अन्वेषक



अधीन रंजन चौधरी, सस्वर, कांस

एक्सपर्ट ट्यू स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और वेल बीइंग पर दिया गया है ध्यान

सरकारी स्वास्थ्य तंत्र सुधरेगा, निजी अस्पताल पर घटेगी निर्भरता



डॉ. अंशुमान कुमार
वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ, दिल्ली

महामारी से सबक लेते हुए सरकार ने आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र का विशेष ख्याल रखा है. पिछले साल के मुताबिक इस साल स्वास्थ्य बजट में 137 फीसदी का इजाफा किया गया है.



यानी 137 प्रतिशत का इजाफा किया गया है.

विकसित देशों, विशेषकर यूरोपीय देशों से इसकी तुलना करें, तो अभी भी हम बहुत पीछे हैं. ज्यादातर यूरोपीय देश अपनी जीडीपी का सात से नौ प्रतिशत तक स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं, लेकिन यह अच्छी पहल है और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गयी है. स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्य रूप से तीन बातों पर फोकस किया गया है- प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और वेल बीइंग. पहले हेल्थ में केवल क्यूरेटिव पर फोकस किया जाता था, यानी कोई बीमार हो, तो उसका कैसे इलाज हो जाये. प्रिवेंटिव यानी बीमारियों की रोकथाम पर खासकर, जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों, जैसे हृदय संबंधी, डायबिटीज, कैंसर और हाइपरटेंशन आदि पर हम फोकस करें, तो देश का बहुत बड़ा खर्च इससे बच सकता है.

प्राथमिक से उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर

हमारे यहां स्वास्थ्य तंत्र तीन स्तरों पर बंटा हुआ है- प्राथमिक, सामुदायिक और उच्च स्तर के स्वास्थ्य केंद्र. गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है. अगर विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकता और जिम्मेदारी तय कर दी जायेगी, तो बड़े अस्पतालों का बोझ कम हो जायेगा और मरीजों को भी सहूलियत होगी.

इस बार बजट में बीमारियों की रोकथाम पर भी बात कही गयी है. जब सरकारी तंत्र मजबूत होगा, तो निजी अस्पताल इतनी मनमानी नहीं कर पायेंगे. तीसरी बात, वेल बीइंग यानी सलामती की है. शारीरिक व मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के साथ लोग कैसे स्वस्थ रह सकें, इस बात पर फोकस किया गया है. इसमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, युनानी, सिद्धा, होम्योपैथ सबको बेहतर बनाने की योजना पर काम किया जायेगा. इस बार प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना घोषित हुई है. समावेशी स्वास्थ्य व्यवस्था लाने की बात कही गयी है, जिसके लिए तकनीक का सहारा लेकर पोर्टल आदि की व्यवस्था की जायेगी. आज की जसूरतों के मद्देनजर यह बहुत आवश्यक है. पोर्टल से जुड़ने के बाद दूरदराज के इलाकों में भी स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता बढ़ेगी.

खाद्यान्न : सिल्वेडी बिल 5.96 लाख करोड़ रहने का अनुमान

एजेंसियां नयी दिल्ली

खाद्य, उर्वरक, रसोई गैस सिल्वेडी और कैंरोसिन तेल पर सिल्वेडी खर्च चालू वित्त वर्ष में 5.96 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचने का अनुमान है. यह बजट अनुमान का करीब ढाई गुना है. सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से गरीब परिवारों को मुफ्त में अतिरिक्त खाद्यान्न का वितरण किया था, जिसका सिल्वेडी बिल पर साफ दिखाने दे रहा है. फरवरी 2020 में सरकार ने सिल्वेडी खर्च 2,27,794 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया था. उस समय देश में कोरोना वायरस नहीं फैला था. इस महामारी की वजह से सभी बजट अनुमानों में बड़ा संशोधन हुआ है. अगले वित्त वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न, उर्वरक और एलपीजी तथा कैंरोसिन पर सिल्वेडी का खर्च बिल 4.3 प्रतिशत घटकर 3.36 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. वित्त वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमान के अनुसार, सिल्वेडी बिल 5,95,620.23 करोड़ रुपये रहेगा. पहले इसके 2,27,793.89 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया था. आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 के संशोधित अनुमान में खाद्य सिल्वेडी 4,22,618.14 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.

09

बायो सेफ्टी लेवल-3 लैब बनाये जायेंगे

॥ रामकाज की अलख जगा रहा लक्ष्मण ॥



जोधपुर @ जागरूक जनता। राम मंदिर निधि समर्पण अभियान आज देश-विदेश में हर गली मोहल्ले में उत्साहपूर्ण वातावरण में चल रहा है। इसी अभियान को हर व्यक्ति तक ले जाने में लिए हर घर अभियान से जुड़े इसलिए शहर की हर गली मोहल्ले में जाकर अलख जगाने का कार्य कर रहे हैं विहिप के लक्ष्मण परिहार। स्कूटर पर आगे राम मंदिर का मॉडल विशेष रूप से तैयार करा कर रख भगावा झंडों से सजाकर दुर्गाहिया पर ही रंडियो सेट करना कर राम नाम की धुन बजाते हुए हर क्षेत्र में पहुंच लोगों को राम मंदिर अभियान से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। लक्ष्मण परिहार बताते हैं कि पहले आमी में रह कर देश की सेवा की और अब सेवानिवृत्त हो गया तो राष्ट्र धर्म के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। परिहार प्रतिदिन सुबह बजे से निकलते हैं और शाम को ही वापस घर आते हैं। परिहार ने बताया कि इस कार्य के लिए 25 हजार स्वयं खर्च वहन किए और राम कार्य करने का अवसर जीवन में प्रथम बार मिला है फिर कभी ऐसा अवसर नहीं आया इसलिए सभी कामों को छोड़ यह समय सिर्फ प्रभु के लिए ही अर्पित करना है। लोगों ने तो अपने प्राणों की आहुति दी लेकिन हमें अब सिर्फ धन का ही समर्पण करना है उसमें पीछे नहीं रह कर बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने की जरूरत है। हर जगह लोगों द्वारा रामभक्त का स्वागत किया जा रहा है।

हर गली घर-घर घूमने कार्यकर्ता, 30 से अधिक बच्चों ने भेंट किये अपने गुल्लक



जोधपुर @ जागरूक जनता। श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान का हर घर महानजसंघ अभियान का आगाज जबरदस्त उत्साह से हुआ। हर गली मोहल्ले में रामभक्तों का मेला सा नजर आया और हर जगह लोगों ने रामभक्तों का स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अल सुबह से ही हर तरफ गली मोहल्ले में 5-5 की टोली बनाकर संघ विहिप के कार्यकर्ता हर घर में सम्पर्क कर लोगों से निधि समर्पण करा रहे हैं। नंदलाल भाटी ने बताया कि सरदारपुरा में सत्संग भवन के बाहर मांग कर खाने वाले भिक्षुओं ने भी उत्साह के साथ समर्पण किया। महानगर की सयाजिका प्रीति गौतम ने बताया कि अभियान में शिल्पा अग्रवाल के नेतृत्व में महिलाओं ने भी सहयोग किया। जिसके तहत गली में सफाई कर्मचारी, सब्जी टोला लगाने वालों से निधि समर्पण लिया गया। कीर्ति नगर में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निधि समर्पण कार्य का शुभारंभ नन्दी बालिका के हाथों भगवान विदेहव्रत महादेव से प्राप्त हुआ। राम जन्मभूमि निधि संग्रह में सचिव नगर बस्ती में घर-घर जाकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हेतु निधि संग्रहण किया गया कीर्ति नगर प्रचार प्रमुख सवाई सिंह राजपुरोहित पवन दायीय कमल दायीय विनोद सोनी ने सहयोग किया। नगर में निर्माणधीन भवन का कार्य कर रहे मजदूर वर्ग के लोगों ने कहा कि अयोध्या में बन रहे जन्मभूमि महतीर्थ का हम भी हिस्सा बन जाए और कुछ नहीं कर सकते तो राम सेतु की गिलहरी बन जाए उन लोगों के द्वारा यह आशा रखकर मन में एक नई ऊर्जा का संघार हुआ। विहिप के लक्ष्मण परिहार ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के राम मंदिर निधि समर्पण अभियान में मातृ शक्ति की भूमिका के तहत विहार गौरीया का आयोजन सरदारपुरा के सत्संग भवन में हुआ। मातृ शक्ति प्रमुख विदेहव्रत भी परिहार ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रान्त संगठन मंत्री प्रयाकर इंद्रा लाल व पुत्र राम प्रसाद जी महाराज बड़ा रामद्वारा सुरसागर के सनिध्य में हुआ। अध्यक्षता आशा जोशी व विशिष्ट अतिथि समाजसेविका भूमि कृपालनी थी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों ने अपने गुल्लक राम मंदिर निधि के लिए समर्पित किये। संचालन माला सोनी ने किया।

भारत ही नहीं दुनियां ने आयुर्वेद को अपनाया-प्रो.संजीव शर्मा



जयपुर @ जागरूक जनता। आयुर्वेद अपार है। यह हजारों वर्षों से चल रही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। वर्तमान समय कोविड-19 वैश्विक महामारी के संकथाम में भी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व ने आयुर्वेद के चिकित्सकी परिणामों को स्वीकार कर आयुर्वेद को अपनाया। यह बात राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विवि के कुलपति प्रो.संजीव शर्मा ने शिष्यापुस्तक संस्कार कार्यक्रम में छात्रों के समक्ष कही। प्रो.शर्मा ने संस्थान में नव आगुतक छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि आयुर्वेद पद्धति का क्षेत्र बहुत विशाल है। आयुर्वेद को किसी भी प्रकार से कम नहीं समझे। आयुर्वेद में विश्वास रखें, निष्ठा पूर्वक अध्ययन करके एक कुशल आयुर्वेद चिकित्सक बनें। गौरतलब है कि नव आगुतक छात्रों का शिष्यापुस्तक कार्यक्रम 15 दिन तक रहेगा। इस दौरान पीएचडी डीन स्टूडीस प्रो.के.शंकर राव, डीन युजी प्रो.मीता कोटिका, संयुक्त निदेशक जन प्रकाश शर्मा, संरक्षक प्रो.राममूर्ति, विभागाध्यक्ष डॉ.छात्राजी यादव, डीन छात्रकल्याण डॉ.सुनील यादव, एनएसएस संरक्षक डॉ.संजय अग्रवाल, एनएसएस प्रिन्सिपल डॉ.महेन्द्र प्रजापति, डॉ.सन्दीप लहाड़ी डॉ.गुलाब पनानी,डॉ.सुदीप रथ,डॉ.सारीका यादव, डॉ.भानुप्रकाश सिंह,डॉ.इंशा हर्षानी, डॉ.धर्मन चौधरी,एम.डी.स्करल,डॉ.दीपक शर्मा, डॉ.सुराम कडवा,डॉ.अशोक चौधरी,डॉ.दिनेश शर्मा,डॉ.सुमित बेरवाल,डॉ.पंकज छिप्रा,डॉ.भूपेंद्र शर्मा चांदवास उपस्थित रहे।

बोराणा समाज के प्रदेश मंत्री नियुक्त



सीकर @ जागरूक जनता। गाड़ीया लोहार समाज के प्रदेश स्तरीय सीकर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष कालूराम फौजी बाबा व प्रदेश अध्यक्ष सावरलाल के द्वारा पाली जिले के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की नहीं, बल्कि पूरे विश्व ने आयुर्वेद के चिकित्सकी परिणामों को स्वीकार कर आयुर्वेद को अपनाया। यह बात राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विवि के कुलपति प्रो.संजीव शर्मा ने शिष्यापुस्तक संस्कार कार्यक्रम में छात्रों के समक्ष कही। प्रो.शर्मा ने संस्थान में नव आगुतक छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि आयुर्वेद पद्धति का क्षेत्र बहुत विशाल है। आयुर्वेद को किसी भी प्रकार से कम नहीं समझे। आयुर्वेद में विश्वास रखें, निष्ठा पूर्वक अध्ययन करके एक कुशल आयुर्वेद चिकित्सक बनें। गौरतलब है कि नव आगुतक छात्रों का शिष्यापुस्तक कार्यक्रम 15 दिन तक रहेगा। इस दौरान पीएचडी डीन स्टूडीस प्रो.के.शंकर राव, डीन युजी प्रो.मीता कोटिका, संयुक्त निदेशक जन प्रकाश शर्मा, संरक्षक प्रो.राममूर्ति, विभागाध्यक्ष डॉ.छात्राजी यादव, डीन छात्रकल्याण डॉ.सुनील यादव, एनएसएस संरक्षक डॉ.संजय अग्रवाल, एनएसएस प्रिन्सिपल डॉ.महेन्द्र प्रजापति, डॉ.सन्दीप लहाड़ी डॉ.गुलाब पनानी,डॉ.सुदीप रथ,डॉ.सारीका यादव, डॉ.भानुप्रकाश सिंह,डॉ.इंशा हर्षानी, डॉ.धर्मन चौधरी,एम.डी.स्करल,डॉ.दीपक शर्मा, डॉ.सुराम कडवा,डॉ.अशोक चौधरी,डॉ.दिनेश शर्मा,डॉ.सुमित बेरवाल,डॉ.पंकज छिप्रा,डॉ.भूपेंद्र शर्मा चांदवास उपस्थित रहे।

आईसीएआई ने घोषित किया सीए फाइनल नवंबर 2020 का परिणाम

सड़क हादसे में रीढ़ की हड्डी टूटी, लकवा हुआ, नहीं छोड़ी पढ़ाई, देश में आया तीसरा स्थान

आइसीएआई ने घोषित किया सीए फाइनल नवंबर 2020 का परिणाम, जयपुर के स्टूडेंट्स ने लहराया परचम, शहर के 10 स्टूडेंट्स ने न्यू स्कीम और दो कैडिडेट्स ने ओल्ड कोर्स में स्कोर की ऑल इंडिया रैंकिंग, जयपुर चैप्टर का ओल्ड सिलेबस का रिजल्ट 25 परसेंट और न्यू स्कीम का रिजल्ट 40.96 प्रतिशत रहा

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.in.com

जयपुर। इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की ओर से सोमवार को सीए फाइनल (ओल्ड और नई स्कीम) नवंबर 2020 का रिजल्ट जारी किया गया। सीए फाइनल ओल्ड स्कीम में जयपुर से इस बार शीर्ष (ऑल इंडिया रैंकिंग) 50 में से 2 स्टूडेंट्स ने अपनी जगह बनाई है। वहीं, सीए फाइनल नई स्कीम में कुल 10 स्टूडेंट्स ने टॉप 50 रैंकिंग में अपना स्थान बनाया। जयपुर के कालवाड़ रोड़ निवासी 26 वर्षीय मयंक सिंह ने सीए फाइनल ओल्ड स्कीम में 800 में 489 अंक प्राप्त कर आल इंडिया रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया। मयंक ने बताया कि इससे पहले उन्होंने मई 2017 में सीए फाइनल का एजाम दिया था, लेकिन अगस्त 2017 में एक सड़क हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी। इसके चलते वह नवंबर 2017 का एटैप्ट नहीं दे सके। उन्होंने बताया कि इस घटना के कारण उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाई करना नहीं छोड़ा और आखिरकार सीए फाइनल पास किया। उन्होंने बताया कि स्क्राइब की मदद से उन्होंने पेपर दिया और यह उनका चौथा एटैप्ट था। मायक अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता नौनीहाल सिंह और ममी नीता सिंह को देते हैं।



जयपुर के स्टूडेंट्स ने लहराया परचम

वहीं, आशिमा राठौड़ ने 444 अंक प्राप्त कर आल इंडिया 13वीं रैंक हासिल की। ओल्ड स्कीम में प्रथम स्थान पर तमिल नाडु, सालेम के इस्पाकिराज ए और द्वितीय स्थान पर चेन्नई की श्रीगंगा आर रही। नई स्कीम में मुंबई की कोमल किशोर जैन ने फर्स्ट रैंक, सरत के मुदित अग्रवाल ने सेकंड और मुंबई की राजवी अश्विनी नयवाणी ने थर्ड रैंक हासिल की। सीए फाइनल नई स्कीम के तहत जयपुर की प्रियांका जैन ने 800 में से 578 अंक प्राप्त कर आल इंडिया छठी रैंक हासिल की। इसी प्रकार गुजजैन जैन ने 556 अंकों के साथ 14वीं रैंक और नारायण इवर 547 मार्क्स के साथ 18वीं रैंक हासिल की। न्यू कोर्स में है रेशनी शिवारमणी की ऑल इंडिया 27वीं, हर्ष मिश्र की 33वीं, तन्मय गुप्ता की 35वीं, निखिलेश जैन की 39वीं, निरकुंज माहेश्वरी की 42वीं, नैनी अग्रवाल की 46वीं और यश खंडेलवाल की 48वीं रैंक है। आइसीएआई जयपुर चैप्टर के चेयरमैन अनिल कुमार यादव ने बताया कि इस बार जयपुर से ऑल इंडिया रैंक ज्यादा आई है और जयपुर का ओल्ड ऑल रिजल्ट भी अच्छा रहा है। सीए ओल्ड सिलेबस में ऑल इंडिया का रिजल्ट 5.84 परसेंट और न्यू स्कीम में 14.47 प्रतिशत रहा। वहीं जयपुर चैप्टर का ओल्ड सिलेबस का रिजल्ट 25 परसेंट और न्यू स्कीम का रिजल्ट 40.96 प्रतिशत रहा। उन्होंने बताया कि ओल्ड सिलेबस में जयपुर चैप्टर के फर्स्ट रैंक का रिजल्ट 22.12 और सेकंड रैंक का 42.03 प्रतिशत रिजल्ट रहा। दोनों रैंक मिलकर 25 प्रतिशत रिजल्ट रहा। वहीं, न्यू स्कीम के फर्स्ट रैंक का रिजल्ट 10.27, सेकंड रैंक का 33.65 और दोनों गुण का रिजल्ट 40.96 प्रतिशत रहा।

औद्योगिक क्षेत्रों में जल्द लागू हो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net.com

जयपुर। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों के चहुमुखी विकास हेतु सर्विस इंडस्ट्री के सहयोगी कार्यों के लिए परमिशन देकर उद्योगों को शीघ्र राहत देने की जरूरत है। भारत के कई प्रदेशों में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2020 लागू की है। नई पॉलिसी के तहत इंडस्ट्रियल एरिये में पेट्रोल पंप, कंटा, इंटरनेटमेंट पार्क, एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट, होटल व दुकानें, अस्पताल, मल्टीप्लेक्स, वेयर हाउसिंग, रिटेल आउटलेट बनाने की परमिशन दे दी है। इस पॉलिसी के तहत दिल्ली व हरियाणा में तो इस तरह की पॉलिसी बनाकर लागू भी हो चुकी है। राजस्थान सरकार को रीको इंडस्ट्रियल एरिये में भी जमीन को बेचने का दर्जा देने एवं लैंड यूज को (पेट्रोल पंप, धर्मकंटा व अन्य औद्योगिक कार्यों के लिए) पहले की भांति परिवर्तित करने की स्वीकृति दी जानी चाहिए तथा इसको इंडस्ट्रियल लैंड का दर्जा दिया जाए। इससे रीको में विकास कार्यों के साथ उद्योगों को गति मिलेगी। सम्पूर्ण राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में जयपुर एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके चारों ओर बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र बसे हुए हैं इन इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जो लगभग 50 साल पुराने हैं और इंडस्ट्रियल के रूप में कटे हुए हैं जैसे 22 गोदाम, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र व अन्य

कई क्षेत्र हैं जो की शहरी सीमा के अन्दर आ गए हैं वहां पर अत्यधिक पोलूशन व रजिडैंशियल क्षेत्रों के कारण इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चलना सम्भव नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में सरकार को यह चाहिए की उन उद्योगों के द्वारा ही वहां पर सर्विस इंडस्ट्री को प्रमोट करे साथ ही वहां जो नॉन पॉल्यूटेड इकाइयां स्थापित है उनको स्पेशल छूट प्रदान की जाए, जिससे की उस क्षेत्र में जो जगह है जो की उद्योगों के लिए काम नहीं आ पा रही है उस स्थान पर वहां उद्योगों की जो सहयोगी गतिविधियां हैं उनको उद्योगों का दर्जा दिया जाए, जिससे इंडस्ट्रियल क्षेत्रों का और विकास होगा और वहां पर ग्रीन इंडस्ट्रियल यूनिट्स चलने से एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण होगा।

नई दिल्ली में महिला कोविड योद्धा के रूप में प्रदेश की ईशरत सम्मानित

जयपुर @ जागरूक जनता। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग के 29 वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में राजस्थान की महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती ईशरत बानो को "महिला कोविड योद्धा" के वास्तविक हीरो का सम्मान स्वरूप प्रशंसा पत्र व शिल्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर "महिला कोविड योद्धाओं वास्तविक हीरो का सम्मान समारोह में राजस्थान सहित मध्यप्रदेश, झारखंड, मिजोरम व तेलंगाना राज्य की एक-एक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का चयन कर उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में महिला आयोग के चेयरपर्सन राकेश शर्मा द्वारा कोविड-19 के दौरान महिलाएं एवं बाल विकास विभाग के तहत समेकित बाल विकास सेवा की अग्रणी पक्ति के महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 के दौरान किये गये उत्कृष्ट कार्य को प्रशंसा भी की।

एईएन कार्यालय में ही सुनी जाएगी बिजली की समस्याएं

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net.com

जयपुर। जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक नवीन अरोड़ा ने जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया। अरोड़ा ने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के साथ उनकी छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए सहायक अभियंता कार्यालय में ही उनकी सुनवाई की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब ऐसी व्यवस्थाएं की जाएगी, जिससे फील्ड में सब-डिवीजन में बैठे अधिकारी उपभोक्ताओं की समस्याओं को अच्छी तरह सुने और उनका निस्तारण करें। इससे लोगों को एम्स ऑफिस तक अपनी शिकायत लेकर नहीं आना पड़े। इसके साथ ही विद्युत दुर्घटनाओं की दर को शून्य करने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। जनता और अधिकारियों के सर्गमिलित प्रयास से यह संभव हो पाएगा, इस दिशा में काम किया जाएगा, जनता को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। उपभोक्ताओं के संतुष्टि स्तर को बढ़ा कर व बिजली चोरी को रोककर लॉसेज को कम किया जाएगा। उपभोक्ताओं से सामंजस्य करके सर्वमिंत प्रयास से राजस्व वसूली के लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। लोगों की बिजली के कनेक्शन समय पर किये जाएंगे। अरोड़ा इससे पहले जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम में निदेशक तकनीकी और जयपुर डिस्कॉम में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। नवीन अरोड़ा का निगम के अभियंताओं, अधिकारियों और कर्मियों ने सम्मान किया।

जयपुर रत्न सम्मान समारोह सौजन 3 का पोस्टर विमोचन

समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहना जरूरी है-पारीक

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net.com

जयपुर। शक्ति फिल्म प्रोडक्शन और हेल्प इंडिया ऑनलाइन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम जयपुर रत्न सम्मान समारोह सौजन 3 का पोस्टर विमोचन वैशाली नगर स्थित रिटिजी स्कूल में किया गया।

कार्यक्रम के आयोजक अंबालिका शास्त्री और एमएफए-डॉ पवनकुमार पारीक और डॉ जगदीश पारीक ने बताया कि समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहना आवश्यक है। साथ ही आवश्यक है उन लोगों का सम्मान जो इस समाज तथा देश को समर्पित होकर श्रेष्ठ कार्य कर दूसरों से अलग अपनी पहचान बनाते हैं। इनहीं भावों को लेकर शक्ति फिल्म प्रोडक्शन और हेल्प इंडिया ऑनलाइन हरवर्ष की भांति जयपुर रत्न सम्मान समारोह का तृतीय संस्करण लेकर आया जाएगा, जिसका परिणाम प्रेस कॉन्फेंस के विभिन्न क्षेत्रों में समर्पित भाव से श्रेष्ठ कार्य करने वाली गणमान्य विभूतियों व प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा।



अंबालिका शास्त्री और एमएफए डॉ पवनकुमार पारीक और डॉ जगदीश पारीक ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर रत्न सम्मान समारोह का तृतीय संस्करण जल्द आयोजित होगा, जिसमें समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को तारास्कर उन्हें अलग व विशेष पहचान प्रदान की जाएगी। इस सम्मान के नामिनेशन के लिए 25 फरवरी अंतिम तिथि रखी गई है। नामिनेशन के माध्यम में प्रान्त हुड प्रविष्टियों को निर्माण मंडल द्वारा चयनित किया जाएगा, जिसका परिणाम प्रेस कॉन्फेंस के माध्यम से 1 मार्च तक घोषित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सम्मान समारोह के साथ ही विभिन्न मॉडलों द्वारा डिजाइनर शोकेसिंग व एनजीओ के अनाथ बच्चों द्वारा फैशन वॉक किया जाएगा, जिसके उपरांत इन बच्चों को उपहार दिए जाएंगे। हेल्प इंडिया के राष्ट्रीय सचिव श्यामासिंह शेखावत ने बताया कि हेल्प इंडिया सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं उत्कृष्ट प्रतिभाओं को तारास्कर के लिए सदैव कार्यरत रहेगा। कार्यक्रम आयोजक अंबालिका, एमएफए डॉ पवनकुमार पारीक और डॉ जगदीश पारीक ने बताया कि पोस्टर विमोचन में कार्यक्रम के मैनेजिंग डिप्युटी रिकु सिंह गुर्जर, हेल्प इंडिया में प्रिविटेड हेल्थ प्रभाती कन्हैयालाल खेरथल, हेल्प विंग के प्रभारी शंकर लाल प्रदेश अध्यक्ष डॉ श्रीधर आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे।

ANCHOR परिवहन विभाग का नाम बदलेगा

परिवहन विभाग का नाम बदलकर परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग करने की तैयारी, सड़क दुर्घटनाओं पर कंट्रोल का टास्क

परिवहन मंत्री की घोषणा ,सड़क दुर्घटना के घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले होंगे सम्मानित हर जिले में बनेगा टैफिक पार्क, स्पीड लिमिट के उल्लंघन करने वालों को मोबाइल पर चालान



जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net.com

जयपुर। राज्य सरकार जल्द परिवहन विभाग का नाम बदलकर परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग करने की तैयारी कर रही है। सड़क सुरक्षा की अहमियत और बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण का हवाला देकर सरकार ने नाम बदलने की कवायद शुरू की है। परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने सभी आरटीओ, डीटीओ के साथ वीसी के जरिए समीक्षा बैठक के बाद कहा कि विभाग का नाम बदलने की कवायद की जा रही है ताकि सड़क सुरक्षा पर फोकस किया जा सके। विभाग का नाम बदलने के साथ अब थोड़ा काम भी बदलेगा और रोड सेप्टी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। परिवहन मंत्री खाचरियावास ने बताया कि रोड सेप्टी कार्टिसिल की बैठक में यह निर्णय किया जा चुका है कि सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को कम करने

के लिए आवश्यकतानुसार नई एम्बुलेंस की खरीद, ब्लैक स्मॉट टीक कराना जैसे काम किए जा सकेंगे। सड़कों के खुदू भरवाए जाएंगे और ऐसी बेरिंकिंग खाचरियावास ने सभी आरटीओ, डीटीओ के साथ वीसी के जरिए समीक्षा बैठक के बाद कहा कि विभाग का नाम बदलने की कवायद की जा रही है ताकि सड़क सुरक्षा पर फोकस किया जा सके। विभाग का नाम बदलने के साथ अब थोड़ा काम भी बदलेगा और रोड सेप्टी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। परिवहन मंत्री खाचरियावास ने बताया कि रोड सेप्टी कार्टिसिल की बैठक में यह निर्णय किया जा चुका है कि सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को कम करने

के लिए आवश्यकतानुसार नई एम्बुलेंस की खरीद, ब्लैक स्मॉट टीक कराना जैसे काम किए जा सकेंगे। सड़कों के खुदू भरवाए जाएंगे और ऐसी बेरिंकिंग खाचरियावास ने सभी आरटीओ, डीटीओ के साथ वीसी के जरिए समीक्षा बैठक के बाद कहा कि विभाग का नाम बदलने की कवायद की जा रही है ताकि सड़क सुरक्षा पर फोकस किया जा सके। विभाग का नाम बदलने के साथ अब थोड़ा काम भी बदलेगा और रोड सेप्टी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। परिवहन मंत्री खाचरियावास ने बताया कि रोड सेप्टी कार्टिसिल की बैठक में यह निर्णय किया जा चुका है कि सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को कम करने

बजट



जागरूक जनता
jagrukjanta.net
कविता
दिन-एषा कुंभज

हे लोकतंत्र के चौधे खम्भे (मीडिया)
बात एक बतानी है झूठा है ये बजट केंद्र का रपट यही लिखानी है

राशन महंगा घर महंगा महंगी मोटरकार है क्या करोगे इनका साथी जब नहीं कोई रोजगार है रक हूई जनता देशवकी वित्त मंत्री बनो रानी है झूठा है ये बजट केंद्र का रपट यही लिखानी है.....

टेक्सों में राहत नहीं व्यापार जगत को घाटा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम हुए महंगे सरता पर मोबाइल डाटा है ये तो सिर्फ बातें करते मन को नहीं जानी है झूठा है ये बजट केंद्र का रपट यही लिखानी है....

दिल पर हाथ रखना साथी ना हमको बहकना रे क्या है ये जन हित बनार सच हमको बतलाना रे हम तो चलो मुखें ठहरे पर तू तो साथी जानो है झूठा है ये बजट केंद्र का रपट यही लिखानी है....
(लेखक जयपुर से है)

लोग क्या कहेंगे



जागरूक जनता
jagrukjanta.net
कविता
सुनीता शर्मा

"हमेशा एक इर रहता है की लोग क्या कहेंगे,
जिन्हें हम जानते भी नहीं, हम उनकी सोच की फिक्र करते है।
जबकि हमारा मन, दिल, दिमाग जो की हमारे इतने करीब है हम चाह कर भी नहीं सुने।"

तो अब से अपने आप को परेशान करना बंद करिये और "लोग क्या कहेंगे" की बडी को तौं कर, अपने मन की सुनिप, जो अच्छा लगाता है करिये, खुश रहिये,
ये आफका जीवन है इस पर आफका पूरा अधिकार है।
(लेखक जयपुर से है)





परिवहन-उद्योग

बजट 2021-22

पर्यटन को थी जरूरत



2026.77

करोड़ मिला है पर्यटन मंत्रालय को यह पिछले साल से 18% कम है



देश में तीन साल में सात बड़े टेक्सटाइल पार्क बनेंगे

एजेंसियाँ नयी दिल्ली

बजट में देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाने की नीति शुरू करने की घोषणा की. यह भारत को कपड़ा क्षेत्र में पूरी तरह से एकीकृत व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण एवं निर्यात केंद्र बनाने की सरकार की कोशिश का हिस्सा है. सीतारमण ने तीन साल में सात बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाने का लक्ष्य बताया है. इनमें एकिकृत सुविधाएं होंगी. परिवहन में होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने की व्यवस्थाएं होंगी. इससे प्लाग एंड प्ले सुविधा के साथ विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा. निर्यात में वैश्विक स्तर पर अग्रणी कंपनियों के सुजन का मार्ग प्रशस्त करेगी. कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि वृहद

एकीकृत कपड़ा क्षेत्र एवं परिधान (मित्र) पार्क पर विचार चल रहा है. ये पार्क एक हजार एकड़ से अधिक भूखंड पर स्थित होंगे. इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, साइदा सुविधाएं और शोध व विकास लैब भी होंगे. अभी तक पार्क योजना में 59 टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी दी गयी है, जिनमें से 22 तैयार हो चुके हैं. सीतारमण ने कहा कि हम अब नायलॉन थ्रूखला को पॉलिस्टेर व अन्य कृत्रिम धागों के समरूप बना रहे हैं. हम कैप्रोलैक्टम, नायलॉन चिप, नायलॉन धागे पर मूल सीमा शुल्क को एक समान घटाकर पांच प्रतिशत कर रहे हैं. कपास पर सरकारी शुल्क से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है. कच्चे रेशम और रेशम पर शुल्क को 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है.

छठा बड़ा निर्यातक है भारत दुनिया में कपड़े व परिधानों का

1,600 करोड़ की टाक्सिडी शिपिंग कंपनियों को ग्लोबल टैंडर में

लाघु उद्योगों के मौजूदा 50 लाख के पूंजी आधार को बढ़ाकर दो करोड़ होगा. एनसीएलटी की रूपरेखा मजबूत की जायेगी.

एकीकृत प्रतिभूति बाजार संहिता पेश करने का प्रस्ताव. सेबी को गोल्ड एक्सचेंज के नियामक के रूप में अधिसूचित किया जायेगा.

इंडस्ट्री
53,986
करोड़ के राजस्व का अनुमान है अगले वित्त वर्ष में दूरसंचार क्षेत्र से

एमएसएमई
एमएसएमई को राहत देने के लिए कई स्टील उत्पादों पर आयात शुल्क घटाया गया

मोबाइल के सात स्पेक्ट्रम बैंडों की नीलामी एक मार्च से

एविएशन
विमानों को लीज पर देने वाली कंपनियों को टैक्स में छूट संभव

एमएसएमई आवंटन दोगुना कर 15,700 करोड़ रुपये किया गया

2020-21 के बजट में दूरसंचार से 1.33 लाख करोड़ के राजस्व का अनुमान था, सोमवार को संशोधित कर इसे 33,737 करोड़ कर दिया

सरकार ने विमान पड़े पर देने वाली कंपनियों को टैक्स छूट देने का सोमवार को प्रस्ताव किया. एविएशन इंडस्ट्री अपने बढ़ते घाटों के कारण पिछले कई महीनों से भारी दबाव में है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इका की रिपोर्ट के मुताबिक विमानन कंपनियों को इस साल कुल 21,000 करोड़ का भारी नुकसान हुआ.

तांबे के कबाड़ पर कस्टम इयूटी को पांच से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया

राजस्व प्राप्ति में मुख्यतः दूरसंचार ऑपरेटरों से मिलने वाले लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क से मिलने वाली आय शामिल है.

दूरसंचार से राजस्व अनुमान को ऐसे समय घटाया है जब सरकार 3.92 लाख करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम नीलामी की तैयारी कर रही है

राष्ट्रीय रेल योजना से उद्योगों में आएगी जान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1.10 लाख करोड़ का आवंटन किया

भारतीय यातायात व्यवस्था की गंदे रेलवे को लेकर सरकार गंभीर है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए दीर्घ कालीन नेशनल स्कीम का खाका पेश किया. इसका मकसद वर्ष 2030 तक रेलवे सिस्टम को भविष्य के लिए तैयार करना है, ताकि उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जा सके. मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले. माल की कीटनों से दुलाई आसान और तेज होगी. कंपनियों को अपने माल को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने के लिए सड़क परिवहन और ट्रकों पर निर्भरता कम होगी. इससे जहाँ कंपनियों की प्रोडक्शन कोस्ट कम पड़ेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ की रिकॉर्ड राशि की घोषणा की, इसमें से 1.07 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित हैं. पूंजीगत व्यय से रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर, यात्री सुविधाओं के विस्तार और अपग्रेडेशन के लिए रुपये खर्च होंगे. वित्त मंत्री ने उम्मीद जतायी कि पूर्वी और पश्चिमी माल गलियारों (इंडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी) जून, 2022 तक चालू हो जायेंगे. इससे रेलवे का कुल व्यय के जारिये 6500 ट्रेनों की निगरानी की व्यवस्था पहले से चल रही है. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि पीपीपी (सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भागीदारी) के तहत 150 और निजी ट्रेनें, तेजस ट्रेनें चलेगीं, क्विंट डिम कोच ट्रेनें, किफायती थर्ड एसी कोच, स्मार्ट कोच, तापमान नियंत्रित प्रणाली पर काम किया जा रहा है.

सड़कों का जाल

8,500
किलोमीटर के हाइवे प्रोजेक्ट अगले वित्त वर्ष में लागू होंगे

बढ़ेगी कनेक्टिविटी

100
पर्यटन स्थलों और 45 शहरों को नेशनल हाइवे से जोड़ा जायेगा

ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के 100% विद्युतीकरण दिसंबर 2023 तक पूरा होंगे.

यात्रियों के लिए विस्टाडोम एलएचबी कोच लगाये जायेंगे.

18,000 करोड़ से दुरुस्त होगी शहरी यातायात

देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मार्च 2022 तक देश में 8,500 किमी के हाइवे प्रोजेक्ट का आवंटन किया जायेगा. शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 18,000 करोड़ रुपये की योजना की भी घोषणा की. गडकरी ने कहा था कि उनके मंत्रालय का मार्च तक प्रतिदिन 40 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है. पांच साल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) का लक्ष्य 60,000 किमी के हाइवे तैयार करने का है जिसमें 2,500 किमी एक्सप्रेस हाइवे होंगे. इनमें 9,000 किमी के आर्थिक गलियारों और 2,000 किलोमीटर की सामरिक सीमा और तटवर्ती सड़कें होंगी.

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5.54 लाख करोड़ का प्रस्ताव

बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सीतारमण ने पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करते हुए इसे अगले वित्त वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया. प्रमुख मंत्रालयों के तहत 1.10 लाख करोड़ की लगभग 217 प्रोजेक्ट पूरी की जा चुकी है. यह 2020-21 के बजट अनुमानों से 34.5% अधिक है.



व्यावहारिक, तर्कसंगत और प्रगतिशील बजट है. यह अगले 3-4 वर्षों के लिए दिशा देगा. सरकार ने इस बार बुनियादी ढांचे और संपत्ति के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है. सबसे महत्वपूर्ण बात टैक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है और कोई नया सेस नहीं लगाया गया है. **अमितभक्त साहू**, नीति.आय.एम



बजट उन लोगों के साथ विश्वासघात है जो कोरोना महामारी और मंदी की दोहरी मार झेल रहे हैं. कृषि क्षेत्र में आवंटन कम कर दिया गया. एमएसएमई का वादा किया गया, लेकिन मूल्य समर्थन योजनाओं के लिए आवंटन घटा दिया गया है. पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त सेस लगा दिया गया. बेतहाशा महंगाई बढ़ेगी. **सीताराम येचुरी**, महासचिव, माकपा

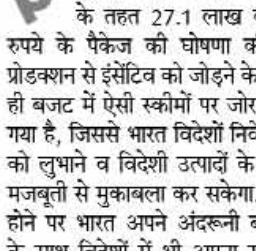
एक्सपर्ट ट्यू

27.1 लाख करोड़ के पैकेज से मिलेगी बाजार को मजबूती

प्रोडक्शन इंसेंटिव बढ़ने से भारत में निवेश के लिए आकर्षित होंगे विदेशी

इस बजट में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है. प्रोडक्शन से इंसेंटिव को जोड़ने के साथ ही बजट में ऐसी स्कैमों पर जोर दिया गया है, जिससे भारत विदेशी निवेशकों को लुभाने व विदेशी उत्पादों के साथ मजबूती से मुकाबला कर सकेगा. ऐसा होने पर भारत अपने अंदरूनी बाजार के साथ विदेशों में भी अपना सामान बेच सकेगा. बजट में विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा. कपड़ा क्षेत्र को और गति देने के लिए सरकार से बजट में सात टेक्सटाइल मेगा पार्क बनाने जाने की घोषणा की है. इससे बाहर के निर्यातकों को भारत में उत्पादन करने के लिए अलग से फैक्ट्री लगाए जाने की जरूरत नहीं होगी. कोई भी छोटा या मध्यम निर्माता भारत में आकर फैक्ट्री की जगह किराये पर लेकर तुरंत उत्पादन चालू कर सकेगा, जिससे उसका खर्च बचता. इससे पहले मलेशिया, थाइलैंड, चीन व अस्सी के देशों में ताहवान जैसे देशों में इस तरह की योजनाओं से अच्छी बढ़ोतरी देखी जा चुकी है. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

उद्योग और निवेश के लिए बहुत अच्छे फैसले



बहुत ही थोड़े समय तक दिखायी देता है. बजट में आत्मनिर्भर भारत व प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी स्कैमों की घोषणा कर एक ऐसी नींव तैयार की गयी है, जिससे आनेवाले पांच वर्षों में भारत विभिन्न क्षेत्रों के बड़े बाजार वाले देशों की सूची में शीर्ष पर पहुंच सकता है. सरकार से बजट में सूक्ष्म, छोटे व मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को विकसित करने के लिए 15,700 करोड़ रुपये दिये गये हैं. साथ ही, इस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग को बढ़ावा देने की बात कही गयी है.

(एफडीआइ) की बात करें, तो इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है. एफडीआइ तंत्र पहले से ही काफी खुला हुआ है. इसके तहत देश के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ मामूली बदलाव किये गये हैं. किसी भी देश में निवेशक दो अहम बातों को ध्यान में रखते हुए निवेश करना पसंद करते हैं- बाजार कितना बड़ा है और वहाँ फैक्ट्री लगाना व काम करना कितना आसान है. भारत का बाजार निवेशकों को हमेशा से

ही लुभाता रहा है, लेकिन यहाँ निवेशक इसलिए नहीं आते थे, क्योंकि यहाँ काम करना मुश्किल था. मेगा पार्क के निर्माण से इस दिशा में सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा. एक ध्यान देनेवाली बात यह भी है कि जब देश में उत्पादन होगा, तो निर्यात भी करना होगा. उत्पादन के लिए बहुत सारी सामग्री बाहर से भी मंगानी होगी. ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वह रेल का हो या रोड का, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

4,000
करोड़ महासागर मिशन के लिए

वित्त मंत्री ने निवेशक चार्टर शुरू करने का दिया प्रस्ताव



प्रीतम बनर्जी
आर्थिक विश्लेषक
उत्पादन से इंसेंटिव को जोड़ने के साथ ही बजट में ऐसी स्कैमों पर जोर दिया गया है, जिससे भारत विदेशी निवेशकों को लुभाने व विदेशी उत्पादों को मजबूती से मुकाबला कर सकेगा.

बजट से राहत



गुड्डे इस बजट से एक ही उम्मीद थी. हर्म लक्षित राजकीय घाटे को लेकर काफी उदावादी होना चाहिए, यह हुआ. -आनंद माहिंद्र, चेयरमैन, महिंद्रा ग्रुप

नया विकास वित्त संस्थान बना, 20 हजार करोड़ मिले

सरकार 20,000 करोड़ की पूंजी से एक विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) स्थापित करेगी. दीर्घकालिक कर्ज देने वाला यह नया वित्तीय संस्थान राष्ट्रीय अवसंरचना विकास कार्यक्रम के लिए 2025 तक अनुमानित 111 लाख करोड़ की की वित्तीय जरूरतों को देखते हुए अहम कदम होगा. डीएफआई को पेशेवर चलायेंगे, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए 7000 प्रोजेक्ट चिन्हित की गयी है. एनआइपी एक अन्वृटी पहल है जिसके तहत देश भर में विद्युत स्तरीय आधारभूत ढांचा तैयार किया जायेगा जिससे सभी नागरिकों की जीवनशैली सुधरेगी.

₹ 1.97 लाख करोड़ का पीएलआइ देगी सरकार

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 पेश करते हुए कहा कि सरकार प्रमुख क्षेत्रों के विस्तार के लिए, वैश्विक स्तर पर अग्रणी उद्योगों को तैयार करने तथा उन्हें पोषित करने एवं युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से अगले पांच वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपये व्यय करने के लिए प्रतिबद्ध है. इससे निवेश आयेगा और रोजगार मिलेगा.

20 साल पर निजी वाहनों की फिटनेस जांच जरूरी

एजेंसियाँ नयी दिल्ली



वित्त मंत्री ने पुराने व प्रदूषण फैला रहे वाहनों को हटाने के लिए स्वच्छिक वाहन-स्कैन नीति (वाहनों को कबाड़ में डालने की नीति) की घोषणा की. उन्होंने बताया कि निजी वाहनों को 20 साल होने पर और कमर्शियल वाहनों को 15 साल होने पर फिटनेस जांच करानी होगी. यह नीति देश की आयात लागत को कम करने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल और ईंधन की कम खपत करने वाले वाहनों को बढ़ावा देगी. नितिन गडकरी ने नीति का स्वागत करते हुए कहा कि इससे 10 हजार करोड़ रुपये के नये निवेश और रोजगार के 50 हजार अवसर सृजित होंगे. इस नीति के दायरे में एक करोड़ से अधिक पुराने 51 लाख हल्के वाहनों के आने का अनुमान है. इसके अलावा 15 साल से पुराने 34 लाख हल्के वाहन और 17 लाख मध्यम व भारी वाहन भी इसके दायरे में आयेगे. ये वाहन नये मॉडलों की तुलना में 10-12 गुना अधिक प्रदूषण फैलाते हैं. गडकरी ने इसके फायदे मिनते हुए कहा कि यह

● वाहन-स्कैन पॉलिसी के दायरे में आयेगे एक करोड़ वाहन
● 10 हजार करोड़ रुपये के नये निवेश की संभावना

बेकार घातुओं के रिसाइकिल, वायु प्रदूषण में कमी, नये वाहनों की बेहतर ईंधन दक्षता के चलते आयात लागत में कमी और निवेश के सही इस्तेमाल का मार्ग प्रशस्त करेगी. गडकरी ने पिछले सप्ताह कहा था कि सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपकरणों के पास मौजूद 15 साल से पुराने वाहनों को कबाड़ करने की नीति जल्दी ही अधिसूचित की जायेगी. एक अप्रैल 2022 से इसे लागू किया जायेगा. इस नीति को सरकार पहले ही मंजूरी दे चुकी है. वित्त मंत्री ने भी कहा था कि पुराने वाहनों को कबाड़ पोषित करने की नीति पर काम जारी है. संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श के बाद नीति की घोषणा की जायेगी.



शिक्षा-रोजगार

पढ़ेंगे और बढ़ेंगे



बजट 2021-22

कहां होगा कितना खर्च



50,000 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर अगले 5 वर्षों में

मॉडल स्कूल



38 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे प्रति मॉडल स्कूल पर, पहले 20 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान था

उच्च शिक्षा के लिए नया आयोग, आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल, 15000 स्कूल बदले जायेंगे मॉडल स्कूल में

पीपीपी मॉडल में खुलेंगे 100 सैनिक स्कूल

केंद्रीय बजट में शिक्षा और स्कूलों के लिए कई नये और खास प्रावधान किये गये हैं. संसद में बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश भर में सरकार 100 नये सैनिक स्कूल बनायेगी. इन स्कूलों का निर्माण पीपीपी मॉडल में किया जाएगा. इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक नया आयोग भी स्थापित करने का निर्णय लिया है. देश में केंद्रीय विद्यालयों के नेटवर्क में भी विस्तार किया जायेगा. वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों की पहुंच भी देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचायी जायेगी.

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान नयी शिक्षा नीति का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि भारत की नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सभी ने स्वीकार किया है. उच्च शिक्षा नीति को अधिक प्रभावी एवं सुलभ बनाने के लिए सरकार एक उच्च शिक्षा कमिशन का गठन करने जा रही है. लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गयी है.

एनजीओ की मदद से चलेंगे सैनिक स्कूल: बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 100 नये सैनिक स्कूल गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मदद से चलाये जायेंगे. इनका संचालन पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जायेगा. आदिवासी इलाकों में शिक्षा पर विशेष जोर: आदिवासी इलाकों के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं. बजट में इस पर ध्यान दिया गया है. यहां शिक्षा के सुधार के लिए करीब 750 एकलव्य स्कूल खोलने का फैसला किया गया है. ये स्कूल कहां-कहां खुलेंगे, यह बाद में घोषित होगा.

इस बार इन पर फोकस

स्कॉलरशिप के लिए वित्तीय मदद बढ़ाई गयी

करीब 4 करोड़ एससी व एसटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए वित्तीय मदद बढ़ायी गयी है. 6 साल के लिए 35,219 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.

मॉडल स्कूल में बदलेंगे सरकारी स्कूल

केंद्र सरकार सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से टक्कर देने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में करीब 15 हजार स्कूलों को आदर्श स्कूलों में बदलेगी. इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधरेगी.



किस मद में कितना आवंटन

उच्च शिक्षा पर 38,350 करोड़ रुपये

स्कूली शिक्षा पर 54,873 करोड़ रुपये

150 नये संस्थानों के निर्माण की मंजूरी डिप्लोमा के लिए

48 करोड़ रुपये खर्च होंगे पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में मॉडल स्कूल के निर्माण में

भाषा के विकास पर जोर

1 भाषा अनुवाद मिशन: पहली बार राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की घोषणा की गयी है. महसूद सरकारी दस्तावेजों को प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना.

2 शोध संस्थान होने बेहतर: सीतारमण ने कहा कि हमारे कई शहरों में विभिन्न अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं, जो सरकार के समर्थन से चलते हैं. उदाहरण के लिए हेदराबाद, जहां तकरीबन 40 मुख्य संस्थान हैं. इसी तरह 9 अन्य शहरों में हम इसी तरह का एक समग्र ढांचा खड़ा करेंगे, जिससे इन संस्थानों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, साथ ही इनकी स्वायत्ता बरकरार रह सके. उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिये एक विशिष्ट अनुदान की शुरुआत की जायेगी.

यहां रोजगार की संभावनाएं

1 ऑटो सेक्टर: कीलक स्ट्रेप पॉलिस्ती आने के बाद लगभग 43,000 करोड़ रुपये का कारोबार बढ़ने की उम्मीद है, जिससे इन क्षेत्रों में नौकरियां बढ़ेंगी.

2 नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति: राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की जायेगी. कई नये स्कूल-कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुलेंगे, जहां नये रोजगार के मौके मिलेंगे.

3 टेक्सटाइल सेक्टर: सरकार द्वारा टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश की घोषणा की गयी है. एक्सपोर्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जायेगा. 7,400 प्रोजेक्ट्स शुरू होने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

नयी शिक्षा नीति से गुणवत्ता वाले कंटेंट होंगे उपलब्ध

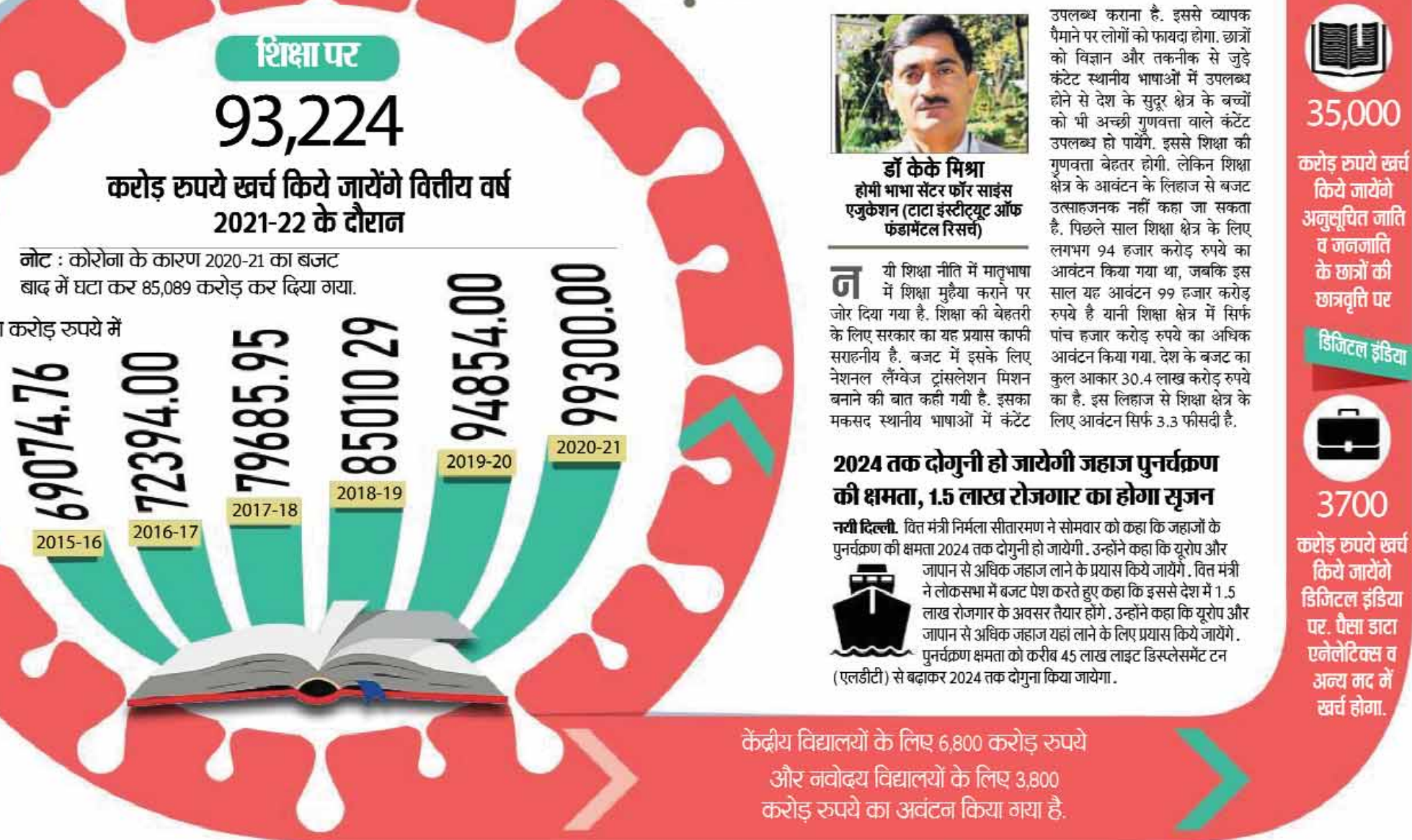


डॉ. केके मिश्रा
होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च)

नयी शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा मुहैया कराने पर जोर दिया गया है. शिक्षा की बेहतरी के लिए सरकार का यह प्रयास काफी सराहनीय है. बजट में इसके लिए नेशनल लैंग्वेज ट्रान्सलेशन मिशन बनाने की बात कही गयी है. इसका मकसद स्थानीय भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध कराना है. इससे व्यापक पैमाने पर लोगों को फायदा होगा. छात्रों को विज्ञान और तकनीक से जुड़े कंटेंट स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होने से देश के सुदूर क्षेत्र के बच्चों को भी अच्छी गुणवत्ता वाले कंटेंट उपलब्ध हो पायेंगे. इससे शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी. लेकिन शिक्षा क्षेत्र के आवंटन के लिहाज से बजट उत्पादनक नही कहा जा सकता है. पिछले साल शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 94 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जबकि इस साल यह आवंटन 99 हजार करोड़ रुपये है. यानी शिक्षा क्षेत्र में सिर्फ पांच हजार करोड़ रुपये का अधिक आवंटन किया गया. देश के बजट का कुल आकार 30.4 लाख करोड़ रुपये का है. इस लिहाज से शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन सिर्फ 3.3 फीसदी है.

2024 तक दोगुनी हो जायेगी जहाज पुनर्वर्धन की क्षमता, 1.5 लाख रोजगार का होगा सृजन

नयी दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि जहाजों के पुनर्वर्धन की क्षमता 2024 तक दोगुनी हो जायेगी. उन्होंने कहा कि यूरोप और जापान से अधिक जहाज लाने के प्रयास किये जायेंगे. वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इससे देश में 1.5 लाख रोजगार के अवसर तैयार होंगे. उन्होंने कहा कि यूरोप और जापान से अधिक जहाज लाने के लिए प्रयास किये जायेंगे. पुनर्वर्धन क्षमता को करीब 45 लाख लाइट डिस्प्लेसमेंट टन (एलडीटी) से बढ़ाकर 2024 तक दोगुना किया जायेगा.



केंद्रीय विद्यालयों के लिए 6,800 करोड़ रुपये और नवोदय विद्यालयों के लिए 3,800 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

असंगठित क्षेत्र सुविधा देने के लिए मजदूरों की जानकारी एकत्र करेगी सरकार

सभी तरह के श्रमिकों के लिए लागू होगा मिनिमम वेज कोड

कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में सबसे अधिक परेशानी असंगठित मजदूरों को उठानी पड़ी थी. इस बार बजट में वित्तमंत्री ने इन पर पूरा ध्यान दिया है. करीब 50 करोड़ श्रमिकों के लिए मिनिमम वेज कोड लागू करने का फैसला किया है. इन्हें भविष्य निधि, स्वास्थ्य और समूह बीमा, पेंशन जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जायेगी. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 2021-22 का बजट पेश किया. बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर वर्ग के श्रमिकों के लिए मिनिमम वेज कोड लागू करने की घोषणा की है. यह प्रवासी और असंगठित श्रमिकों के लिए लागू किया जाएगा. इससे देश के 50 करोड़ के करीब श्रमिकों को लाभ मिलेगा. कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चलते कई फैक्ट्रियों और कंपनियों में ताले पड़ गये. इसका सबसे ज्यादा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ा. इसके लागू होने के बाद उन्हें एक तय समय पर निश्चित रकम मिल सकेगी.



जरीये गिंग वर्कर्स, भवन और निर्माण श्रमिकों के बारे में जानकारी एकत्र की जा सकेगी. प्रवासी एवं श्रमिकों के लिए लांच किये जाने वाले इस खास पोर्टल का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामकारों को दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ऐसे श्रमिक जो अस्थायी रूप से कार्यरत हैं, इनमें गिंग और प्लेटफॉर्म वर्कर शामिल हैं. उन्हें भविष्य निधि, स्वास्थ्य और समूह बीमा, पेंशन जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जायेगी. मिनिमम वेज कोड बिल को 2019 में ही पास कर दिया गया था. इसमें अस्थायी तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों उबर, ओला, स्विगी और जॉमेटो जैसे विभिन्न इ-कॉमर्स व्यवसायों से जुड़े कर्मचारी शामिल होते हैं.

प्रशिक्षु अधिनियम में बदलाव से बढ़ेंगे रोजगार के मौके

युवाओं के लिए अवसरों में वृद्धि के लक्ष्य से सरकार ने अप्रेंटिस कानून में संशोधन और शिक्षा के बाद प्रशिक्षण पानेवालों, स्नातकों और अभियांत्रिकी डिप्लोमा धारकों के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में बदलाव का प्रस्ताव किया है. बजट में वित्त मंत्री ने इस लक्ष्य के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि हमने 2016 में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम शुरू की थी. सरकार अप्रेंटिस कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखती है, ताकि हमारे युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप के अवसरों में और बढ़ोतरी हो सके. अब नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम को नये तौर पर तैयार किया जायेगा, जिसके लिए 3000 करोड़ रुपये से अधिक रखे गये हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि यह पहल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ साझेदारी में की जा रही है, जिसके तहत प्रमाणित कार्यबल के परिनिर्माण के साथ कौशल योग्यता का आकलन, समीक्षा और प्रमाणीकरण किया जायेगा.

पीएफ का पैसा देर से जमा करने की नहीं मिलेगी अनुमति

सरकार ने सोमवार को कहा कि कर्मचारियों के भविष्य निधि जैसे सामाजिक सुरक्षा योगदान को जमा करने में देरी करने वाले नियोजक अपनी आय में कर कटौती का दावा नहीं कर सकेंगे. इस संबंध में वित्त विधेयक 2021 में एक संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियोजक अपने कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा योगदान को समय पर जमा करें. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमने पाया है कि कुछ नियोजक भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति कोष और अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषों के लिए कर्मचारियों के अंशदान को कटौती करते हैं, लेकिन इन अंशदानों को तय समय के भीतर जमा नहीं करते हैं.

देश का आम बजट लोकतंत्र के पवित्र मूल्यों को समर्पित बजट है। यह आत्मनिर्भर भारत की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। यह बजट स्वस्थ व उन्नत भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे युवा वर्ग को सीधे तौर पर फायदा होगा।

- वसुंधरा राजे, पूर्व सीएम

राजस्थान को इस बजट से निराशा ही मिली है। बजट निजीकरण को ब्रेकन, बिजली, बीमा, शिपिंग सहित अनेक क्षेत्रों में बढ़ाने पर केंद्रित है। बजट में किसानों के कर्ज, एसएसीपी की गारंटी पर कुछ नहीं कहा गया।

- सचिन पायलट, पूर्व छिटी सीएम

मोदी सरकार जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। यह 'आम बजट' नहीं 'कारपोरेट परामर्श' का बजट है। पीएम किसान सम्मान निधि को 10,000 करोड़ तक घटा दिया है। इस बजट में राजस्थान को क्या मिला ये हमारे 25 यशस्वी संसद बलाप्यों जिनको प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीद से विजयी करके दिल्ही भेजा है।

- गोविंद सिंह डोटसरा, कांग्रेस प्रदेशध्यक्ष

मोदी सरकार ने इस बजट में सभी पहलुओं को खरौंटे हुए सभी सेक्टरों के मजबूती के साथ विकास पर विशेष ध्यान दिया है। बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट पर विशेष फोकस किया है। सड़क, रेलवे के ढांचे को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया है। साथ ही 2023 तक बॉडोजेन लाइनों को इलेक्ट्रिफिकेशन करने का लक्ष्य भी निश्चित किया है।

- डॉ. सतीश पुनिया, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष



गांव-किसान

ऑपरेशन ग्रीन



बजट 2021-22

2022 तक किसानों की आय होगी दोगुनी

ऑपरेशन ग्रीन स्कीम



22

बर्बाद होने वाली फसलों ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत रहे

माइक्रो इरिगेशन फंड



5,000

करोड़ रुपये और डाले गये माइक्रो इरिगेशन फंड में, सिंचाई की तकनीकों को नार्बाई के तहत दिया जायेगा बढ़ावा



तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किये जाने की भी घोषणा की गयी

नये कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर एलान किया. इस दौरान वित्त मंत्री देश के अनदाताओं के चेहरे पर खुशी लाने के लिए कोई कौर कसर छोड़ने नहीं दिखीं. सीतारमण ने सरकार को किसानों के लिए समर्पित बताते हुए कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है.

उन्होंने कहा कि उत्पादन लागत की तुलना में कम-से-कम 1.5 गुना कीमत सुनिश्चित करने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है. इसके साथ ही किसानों से अनाजों की खरीद और उनको किया जाने वाला भुगतान तेजी से बढ़ा है. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि पिछले छह साल में धान, गेहूं, दालों और कपास जैसी फसलों की खरीद कई गुना बढ़ी है. उन्होंने कहा कि सभी जिलों के लिए उत्पादन की लागत से कम-से-कम डेढ़ गुना कीमत सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी व्यवस्था में व्यापक बदलाव किये गये हैं. सीतारमण ने कहा कि किसानों से खरीद लगातार बढ़ रही है. इससे किसानों को किया जाने वाला भुगतान भी काफी बढ़ा है. वित्त मंत्री ने जैसे ही कृषि क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को गिनाना शुरू किया, विपक्षी सांसद तीनों हालिया कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करने लगे. वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में एमएसपी व्यवस्था के तहत किसानों से की गयी खरीद दिये गये भुगतान के आंकड़े भी गिनाये.

16.5 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण

वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में कृषि ऋण लक्ष्य को 16.5 लाख करोड़ रुपये तक किया जा रहा है. उन्होंने जानकारी दी कि अब स्वामित्व योजना को देशभर में लागू किया जायेगा. इसके साथ ही ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का एलान किया गया है.



75,060
करोड़ रुपये का भुगतान किया गया गेहूं के लिए किसानों को

10,503
करोड़ रुपये दिये गये किसानों को ढलहन उत्पाद के लिए

1,72,752
करोड़ रुपये रही किसानों को धान के लिए भुगतान राशि

बदलाव की आशा

स्वामित्व स्कीम 2021-22 में सभी राज्यों में होगी लागू

- इस वर्ष के शुरू में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत गांवों में संघियों के मालिकों को दिये जा रहे अधिकार के दस्तावेज, अब तक 1,241 गांवों के लगभग 1.80 लाख संघित मालिकों को दिये गये कार्ड, 2021-22 में इस योजना को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने की योजना
- नार्बाई के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपये से बने माइक्रो इरिगेशन फंड में 5,000 करोड़ रुपये और डाल कर इसे दोगुना करने का लक्ष्य
- कृषि और संबद्ध उत्पादों पर किसानों को उचित मूल्य मिले और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 'ऑपरेशन ग्रीन स्कीम' जो कि इस समय केवल टमाटर, प्याज और आलू पर लागू है, के दायरे को बढ़ा कर इसमें जल्दी खराब होने वाले 22 और उत्पादों को किया जायेगा शामिल
- असम और पश्चिम बंगाल में चाय बागानकर्मीयों के कल्याण के लिए 1,000

करोड़ रुपये का प्रस्ताव. वित्त मंत्री ने इस फंड को चाय के बागानों में काम करने वालों, खास कर महिलाओं और उनके बच्चों के लिए देने का खास प्रस्ताव

- गेहूं की खरीद पर 2019-20 में किसानों को 62,802 करोड़ रुपये दिये गये. 2020-21 में किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है. जिन किसानों को लाभ हुआ है, उनकी संख्या भी 2019-20 के 35.57 लाख से बढ़ कर 2020-21 में 43.36 लाख पर पहुंच गयी

- धान की खरीद पर किसानों को 2013-14 में 63,928 करोड़ दिये गये, जो 2019-20 में 1,41,930 करोड़ हो गया. 2020-21 में यह इसके बढ़ कर 1,72,752 करोड़ रहने का अनुमान है. लाभ पाने वाले धान किसानों की संख्या 2019-20 के 1.2 करोड़ से बढ़ कर 2020-21 में 1.54 करोड़ पर पहुंच गयी.

- दालों के मामले में किसानों को 2013-14 में 236 करोड़ का भुगतान किया गया. 2019-20 में यह बढ़ कर 8,285 करोड़ रुपये और 2020-21 में 10,530 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

1.68
करोड़ किसानों का राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के तहत रजिस्ट्रेशन

मछली पालन, पशुपालन व डेयरी पर सरकार का फोकस



वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2021 का आम बजट पेश करते हुए पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन के लिए कई घोषणाएं की हैं. मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश में पांच नये फिश हार्बर शुरू करने की योजना है. कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, पेटुआघाट को फिश हब के रूप में विकसित किया जायेगा. सीवीडी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में सीवीडी पार्क विकसित किया जायेगा. वित्त मंत्री ने बताया कि भारत, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और एक्वाकल्चर उत्पादन के साथ ही

अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन में भी दूसरे स्थान पर है. साल 2018-19 के दौरान देश का मछली उत्पादन 137 करोड़ टन था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का योगदान 95 लाख टन और समुद्री क्षेत्र का योगदान 41 लाख टन का था. केंद्रीय बजट 2020-21 में पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन के लिए 3289.13 करोड़ रुपये दिये गये थे. केंद्रीय मत्स्यपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी पशुपालन के मुताबिक, देश में गावों की संख्या 14.51 करोड़ है, जबकि गोधन करीब 18.25 करोड़ हो गयी है. देश में बैंग की आबादी 10.98 करोड़ है. दुधारु पशुओं (गाय और भैंस) की आबादी 12.53 करोड़ है.

एग्री इन्फ्रा सेस का एलान, आज से लागू

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में, कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कुछ चीजों पर एग्रीकल्चर इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाने का एलान किया. यह नया एग्री इन्फ्रा सेस मंगलवार (2 फरवरी, 2021) से लागू होगा. कच्चे तेल पर 17.5% कृषि सेस, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20% का सेस लगाया है. ग्राहकों पर कीमतों का अतिरिक्त भार न पड़े इसके लिए इन पर बेसिक सीमा शुल्क (बीसीडी) में कटौती की गयी है. इन चीजों में सेब (15%), एल्कोहॉलिक पेय पदार्थ (50%), कच्चे खाद्य तेल (15%), कोयला (1%), अमेनियम नाइट्रेट (2.5%), मटर, काबुली चना, बंगाल चना, मसूर (10%) फसलें शामिल हैं.



(50%), कच्चे खाद्य तेल (15%), कोयला (1%), अमेनियम नाइट्रेट (2.5%), मटर, काबुली चना, बंगाल चना, मसूर (10%) फसलें शामिल हैं.

2.5 प्रतिशत से 100 फीसदी तक लगाया गया सेस

| उत्पाद | एग्री इन्फ्रा सेस | उत्पाद | एग्री इन्फ्रा सेस |
|--------------------------|-------------------|------------|----------------------|
| छूब पाम ऑइल | 17.5% | कोयला | 1.5% |
| छूब सोयाबीन | 20% | काबुली चना | 30% |
| सूरजमुखी | 20% | मटर | 10% |
| एल्कोहॉलिक पेय पदार्थ | 100% | चना | 50% |
| गोल्ड, सिल्वर और डोर बार | 2.5% | मसूर | 20% |
| सेब | 35% | पेट्रोल | 2.5 रुपये प्रति लीटर |
| स्पेसिफाइड फर्टिलाइजर | 05% | डीजल | 4 रुपये प्रति लीटर |

कृषि बजट 5.63% बढ़ा, आधा हिस्सा पीएम-किसान योजना को

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को वर्ष 2021-22 के लिए 5.63% अधिक यानी 1,31,531 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है और इसका आधा हिस्सा प्रधानमंत्री-किसान योजना पर खर्च किया जायेगा, जबकि कृषि-आधारभूत ढांचा कोष एवं सिंचाई कार्यक्रमों के लिए धनराशि की उपलब्धता में मामूली वृद्धि की गयी है. प्रमुख केंद्रीय योजनाओं में, पीएम-किसान के लिए 65,000 करोड़ रुपये का एक बड़ा आवंटन किया गया है, जिसके तहत सरकार पंजीकृत किसानों को तीन सप्ताह में 6,000 रुपये प्रदान करती है. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संवर्धन योजना (पीएम-आशा) के लिए आवंटन को अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये किया गया है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाइ) 'प्रति बूंद अधिक फसल' के लिए आवंटन को वर्ष 2020-21 के लिए 2,563 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से बढ़ाकर 4,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है.



एक्सपर्ट व्यु बाजार की कमियों को दूर करने और व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में मिलेगी सहायता

कृषि क्षेत्र में बढ़ावा से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर



ब्रजेश झा
प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली

स्वामित्व योजना की बात भी हुई है, जो एक अच्छा कदम है. लैंड रिफॉर्ड और लैंड ओनरशिप को लेकर गांवों में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं. इसी कारण लैंड मार्केट सही तरीके से विकसित नहीं हो पाये हैं.

इस बजट का पूरा फोकस स्वास्थ्य, रोजगार सृजन और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर है. रोजगार सृजन एक ऐसी चीज है, जो कृषि को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है. कृषि क्षेत्र फलायन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है. फलायन से कृषि के लिए समय पर काम करनेवाले लोग नहीं मिल पाते हैं. चूंकि ग्रामीण इलाके में वर्ष भर रोजगार नहीं मिलता, इसलिए ज्यादातर लोग गांवों से पलायन कर चुके हैं. रोजगार सृजन से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा और सहूलियत मिलेगी. रेगुलेटड मार्केट या एग्रीएमसी मार्केट के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात भी कही है वित्तमंत्री ने. अभी इन मार्केट में बहुत सी कमियां हैं. सरकार उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए सहायता देगी. फसलों की खरीद की बात भी बजट में है. वित्तमंत्री ने अपने भाषण में बताया है कि 2013-14 से लेकर अभी तक गेहूं की सरकारी खरीद बहुत ज्यादा बढ़ी है. कपास की खरीद भी बढ़ी है.



और लैंड ओनरशिप को लेकर गांवों में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं. इसी कारण लैंड मार्केट सही तरीके से विकसित नहीं हो पाये हैं. यदि आपके पास लैंड की ओनरशिप है और इसे लेकर कोई समस्या नहीं है, लैंड रिफॉर्ड सही है, तो इससे लैंड मार्केट को बढ़ावा मिलेगा. लैंड रिफॉर्ड और लैंड मार्केट के सही नहीं होने से कृषि काफी हद तक प्रभावित हुआ है. इसे ऐसे समझिए कि जिनके पास छोटे-छोटे जमीन के टुकड़े हैं, वो काम की तलाश में बाहर चले गये, ऐसे में वे अपनी जमीन की सही देखभाल नहीं कर पाते थे, लेकिन जब स्वामित्व योजना के तहत उनकी उनकी जमीन का स्वामित्व मिलेगा, वे सुरक्षित रह पायेंगे और अपने जमीन को किसी को भी बटाई पर या दूसरी

व्यवस्था पर दे सकेंगे. पांच फिशिंग हार्बर बनाने की भी बात हुई है. वह सब तटीय क्षेत्रों के लिए है. नि:संदेह सरकार के इस कदम से मरीन फिशरीज को बढ़ावा मिलेगा. इस योजना में सी वीड को बढ़ावा देने की भी बात कही गयी है. एक बात और, जलवायु परिवर्तन के कारण मरीन फिशरीज काफी कम होता जा रही थी. ऐसे में सरकार का यह कदम इसे प्रोत्साहित करेगा. मरीन फिशरीज की ही तरह इनलैंड फिशरीज को विकसित करने की दिशा में भी काम करने के लिए सरकार ने कहा है. लेकिन इसके लिए अभी उसने कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं किया है. यह अच्छी बात है कि कृषि के सहायक क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में सरकार कदम उठा रही है.

मूल्यों में काफी उतार-चढ़ाव होता है. ये पेरिऑडल क्रॉप यानी बहुत जल्द खराब होनेवाले फसल हैं, इनके लिए यदि सही इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो किसानों को उनकी उपज का सही पैसा नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ लोगों को वह उपलब्ध नहीं हो पायेगा. इस परेशानी को कम करने के लिए सरकार ने आलू, प्याज और टमाटर की तरह ही 22 अन्य फसलों को भी वरीयता सूची में शामिल करने की बात कही है. इससे इन फसलों को भी बढ़ावा मिलेगा और किसान और उपभोक्ता के बीच जो प्राइस की दूरी है, वह कम होगी. किसानों को फसल का अच्छा दाम मिलेगा. उम्मीद है कि इससे उपभोक्ताओं को भी काम दाम में चीजें उपलब्ध होंगी. उज्वला योजना में एक करोड़ और लोगों को शामिल किया जायेगा, यह अच्छा कदम है. लकड़ी का चिल्ला जलने से वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है. सरकार का यह कदम वायु प्रदूषण में कमी लाने में सहायता करेगा. महिलाओं की स्थिति भी इससे बेहतर होगी.

ई-नाम प्लेटफार्म
1000 और नंदिनों को ई-नाम प्लेटफार्म से जोड़ा जायेगा.

मत्स्य बंदरगाह
05 बंदरगाह कोचि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआघाट को मत्स्य बंदरगाह के रूप में किया जायेगा विकसित

ग्रामीण आधारभूत ढांचे
30,000 करोड़ की जगह 40 हजार करोड़ रुपये ग्रामीण आधारभूत ढांचे के लिए दिये गये

इनसे सशक्त होंगे किसान

धन्य लक्ष्मी योजना
महिला किसानों के लिए 'धन्य लक्ष्मी योजना' का एलान किया गया है, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं से महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जायेगा.

कृषि उद्दान स्कीम
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादों का आयात बढ़ाने के लिए कृषि उद्दान स्कीम. यह काम पीपीपी मॉडल पर होगा.

प्रधानमंत्री कुसुम योजना
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के जरिये किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जायेगा, 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे. 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जायेगा.



उर्वरता बढ़ाने पर नीति
उर्वरता बढ़ाने पर फोकस रखा जायेगा, रासायनिक खाद के इस्तेमाल को कम किया जायेगा और इसका संतुलित इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस बारे में जानकारी दी जायेगी.

'किसान रेल' कोच
दूध, मांस, मछली समेत जल्दी खराब होने वाली चीजों को बचाने के लिए वातानुकूलित 'किसान रेल' कोच चलाये जायेंगे.

एक जिला-एक उत्पाद
बागवानी के लिए एक जिला-एक उत्पाद की तर्ज पर आगे बढ़ा जायेगा, बागवानी से जुड़े किसानों के लिए, जिला स्तर पर योजना लायी जायेगी, उत्पादन बढ़ाने पर जोर.

खेती और सिंचाई
खेती और सिंचाई के लिए इस वित्तीय वर्ष में 2.83 लाख करोड़ का आवंटन. ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये.

कोल्ड स्टोरेज नार्बाई को
देश में मौजूद वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज को नार्बाई अपने अंडर में लेगा. इन्हें नये तरीके से डेवेलप किया जायेगा. नये वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज भी खोले जायेंगे. इसके लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जायेगा.

सुमन राठौड़ झाझड़ कई साहित्यिक सम्मान से सम्मानित

सुंयुं @ जगुरूक जनता। देश के अनेक साहित्यिक मंचों पर अपनी कलम की ताकत से कोरोनाकाल में पहचान बनाने वाली हनुमानगढ़ की सौधी माटी में पत्नी पढ़ी वेदी एवं ससुराल झाझड़ की पावन माटी में पूंरट एवं संस्कारों का भान सम्मान रखने वाली बहु सुमन राठौड़ पत्नी शक्ति सिंह शोखावत को उनकी साहित्यिक सेवा के आधार पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में साहित्य संगम संस्थान बिहार द्वारा आयोजित तीन दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन में उत्कृष्ट योगदान पर राष्ट्र गौरव सम्मान, अभिनव साहित्यिक मंच प्रयागराज द्वारा भारत गौरव सम्मान, राष्ट्रीय कवि संगम कर्नाटक मंच द्वारा काव्य गौरव सम्मान, कलमकार कुंठ साहित्यिक संस्था दिल्ली द्वारा राष्ट्र प्रेमी सम्मान, साहित्य संगम संस्थान झारखंड द्वारा देशप्रेमी सम्मान, वाह वाह क्या बात है अखिल भारतीय कवि मंच मध्यप्रदेश द्वारा राष्ट्र गौरव सम्मान से उत्कृष्ट योगदान पर अलंकृत किया गया। वहीं तरुणोदय मंच के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में उनकी कविता देहन को द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर प्रशंसा पत्र मंच की ओर से दिया गया। साहित्य संगम संस्थान की मुख्य इकाई द्वारा आयोजित परिचर्चा 'मृदित साहित्य श्रेयस्कर या दैनिकिक हृदी साहित्य' पर परिचर्चा प्रवीण सम्मान, कलम बोलती है साहित्य मंच गुजरात द्वारा सखिख्य लेखक सम्मान, साहित्य संगम संस्थान राजस्थान द्वारा उनकी रचना 'हौसलों की उड़ान' पर साहित्य संगम सम्मान एवं छंदाध्यायित प्रतियोगिता में स्वरचित रचना 'वीर सप्त स्वश्रेष्ठ रहने पर साहित्य संगम संस्थान राजस्थान द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। कोरोनाकाल में साहित्य में रूचि एवं लेखन में निरंतरता बनाए रखने वाली सुमन राठौड़ की कई रचनाएं देश एवं अंतरराष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं।

राहत फाउण्डेशन करेगा निःशुल्क शॉर्ट टर्म ब्यूटी क्लासेज का संचालन

जयपुर @ जगुरूक जनता। कोरोना महामारी (कोविड 19), वैधिक महामारी के साथ साथ आर्थिक विषमताओं के रूप में हमारे समक्ष आई है। उक्त महामारी के पश्चात सम्पूर्ण विश्व नोकरी व व्यवसाय में आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति इन आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए निरंतर रूप से प्रयासरत है। राहत आर्थिक फाउण्डेशन महिला सशक्तिकरण, रोजगार व उद्यम के लिए संघर्षरत है वह इसी प्रयास में कदम आगे बढ़ाया है, राहत आर्थिक फाउण्डेशन के फाउंडर एडवोकेट रुचि सेठी व संदीप पारीक ने बताया कि राहत आर्थिक फाउण्डेशन महिला सशक्तिकरण व स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करता आ रहा है। इसी क्रम में महिलाओं को रोजगार व स्वयं के व्यवसाय के अवसर प्रदान करने के लिए राहत आर्थिक फाउण्डेशन, सोम्या जैन मेकअप और के सौजन्य से निशुल्क शॉर्ट टर्म ब्यूटी कोर्स संचालित करने जा रहा है। जस्टसमेंट व कोर्स करने की इच्छुक महिलाएं राहत आर्थिक फाउण्डेशन को रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। रजिस्ट्रेशन पूर्णतः निःशुल्क है। 18 फरवरी से निःशुल्क शॉर्ट टर्म ब्यूटी क्लासेज का संचालन होगा। जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। महिला सशक्तिकरण अर्थात् दूसरी महिलाओं को कार्य करने का अवसर प्रदान करना, उन्हें आगे बढ़ने देना व कोर्स सिर्फ सशक्त महिला ही कर सकती है। एडवोकेट रुचि सेठी व सोम्या जैन ने सशक्त महिलाओं के रूप में अभिप्राय प्रकट किया है व दूसरी महिलाओं को आगे लाने के लिए आर्थिक रूप से निर्भर करने के लिए प्रयासरत हैं।

पाटोत्सव व पौषबड़ा प्रसादी कार्यक्रम संपन्न



चौमू @ जगुरूक जनता। ग्राम मोरीजा के मोहनलाल जी मंदिर में भगवान का पाटोत्सव व पौषबड़ा प्रसादी का आयोजन पुजारी विमल पारीक के सान्निध्य में गुरुवार को हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में पंडित सुदर्शन शर्मा ने भगवान गणेश अंबिका, नवग्रह, पंचलोकपाल, वरुण कलश व मंडलस्थ देवताओं की षोडशोपचार से पूजा-अर्चना करवाई। इसके बाद भगवान के विवाह का पंचमृत से स्नान करके पुरुष सुक व श्री सुक अभिषेक किया गया। मुख्य यजमान हसराज आत्रेय ने संपन्न की पूजन व हवन करवाया। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा की गई एवं पुणहुति के साथ भगवान के हवन। पकौड़ी पुड़ी का भोग लगाया गया। भगवान के गंगार के बाद आरती की गई एवं पंगत प्रसादी का आयोजन किया गया जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। अंजना में मोरीजा गांव के सभी ग्रामीण जन उपस्थित रहे सभी ने भगवान की प्रसादी का आनंद लिया तथा भगवान मोहन लाल जी के असीकृत दर्शन किए और पूजा अर्चना की पूरा मोरीजा गांव भगवान मोहन लाल जी के जयकांठ से गुंज उठा कार्यक्रम में मोरीजा सरपंच मंगल चंद, सौनी उपसरपंच सुदर्शन शर्मा अंजनी कुमार शर्मा विमल अग्रवाल अशोक गीणा सुनील शर्मा ओम प्रकाश मोदी दामोदर प्रसाद मोदी श्याम सुंदर शर्मा आदि ग्राम निवासी मौजूद रहे।

माली समाज विकास समिति के तत्वाधान में नव निर्वाचित अध्यक्ष, पार्षद व पत्रकारों का स्वागत



चौमू @ (सुशील अग्रवाल) जगुरूक जनता। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी व समिति अध्यक्ष तथा mifvs के संरक्षक प्रहलाद सहाय आर्षोपिया के सान्निध्य में आयोजित किया गया, विशिष्ठ अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष विष्णु कुमार सैनी व कोटपोतली नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा सैनी रही। अंजना में नव निर्वाचित सैनी समाज अध्यक्ष नगरपालिका चौमू कोटपोतली व पार्षदों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने ऐतिहासिक जीते के लिए सभी को धन्यवाद दिया। समाज में सार्विक विवाह सम्मेलन के वरु को एफ डी वितरण व पत्रकार बंधुओं का स्वागत किया गया। अध्यक्ष ने सभी आगंतुकों को धन्यवाद दिया। मंच का संचालन मदन लाल मलेरिया व अनिल कुमार सैनी ने किया इस समाजोह में प्रभाती लाल सेक्रेटरी, शंकर लाल माली, ओमकार तंवर, नरेंद्र राम विमलनिलया, बोदुराम तंवर, रामेश्वर पड्या, रामचंद्र टेंट वाले, ओम भगत, मदन लाल करवा, संतोष कुमार इटावा, राजकुमार इटावा, राकेश महार, बन्नी प्रसाद बासा, कमलेश बासा, सुरेश सैनी अचरोल, लक्ष्म प्रसाद, शंकर लाल, बाबू लाल, संवर मल खेजरीली, सीता राम चवौलिया, दिनेश कुमार तंवर, नानू राम सैनी, कालू राम सांखला, घीसा लाल तंवर, रामेश्वर सिंगोदिया, रामेश्वर चवौलिया, सुरज मल तंवर, झुंजा लाल तंवर, रामचंद्र तंवर, महेश तंवर, डॉक्टर मानप्रकाश, चुनी लाल भगत, प्रवीण, बाबू लाल भमेवा, जगदीश चन्द्र अशोपिय, मोहन लाल तंवर, शिबू दुडवाला, सुंदर लाल तंवर, राजू फूलवाल, नाथू राम विष्णालिया, नानग राम तुंडवाल, सुरज मल करवा, मदन करवा, पूर्ण करवा, बाबू लाल तंवर, शंकर विष्णालिया, भानु प्रसाद, आदि गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।

वागनाथ का सहारा बनी कृष्णा सेवा संस्थान

बालोतरा @ जगुरूक जनता। हाउसिंग बोर्ड निवासी 32 वर्षीय विकलांग वागनाथ जो कि 2 साल पहले एक दुर्घटना में अपने दोनों पैरों से लांचार हो गया था, संस्थान अध्यक्ष धर्मदे देवे ने बताया कि दुर्घटना से पहले कनगा मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने वाला वागनाथ परिवार के भरण पोषण के लिए भीख मांगने को मजबूर हो गया, बालोतरा की स्थानीय गलियों में भीख मांगते देखने पर उसने अपनी आप बनी सुनाई तो वास्तुस्थिति को देखते हुए संस्था की तारफ से वागनाथ को दुर्त सहायता पहुंचाई गयी, जिसमें आर्थिक मदद के साथ, मारिक राशन, वागनाथ के संपूर्ण परिवार और तीनों बच्चों के लिए कपड़े, जैकेट देकर उसके 6 माह का बच्चा लाइव बिल का भी भुगतान किया गया, तथा संस्था द्वारा आस पास रहने वाले गरीब बस्तियों में भी कपड़े और खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस कार्य के दौरान धर्मदे देवे के साथ-साथ के सदस्यों में विमल मालवीया, गणपत वैश्य, मंगीलाल खत्री, मुकेश सिंह, जिंदर परमार, राजू माली बिठुजा, मौजूद सुराणा, आनंद देवे सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।

90 शहरी निकायों का रण अध्यक्ष पद पर अंतिम दिन 281 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल

कुचेरा नगरपालिका में कांग्रेस और कुशलगढ़ में बीजेपी का अध्यक्ष निर्वाचन तय, दोनों जगह केवल एक एक नामांकन 7 फरवरी को अध्यक्ष, 8 को उपाध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस ने जिला प्रभारियों और पर्यवेक्षकों को दिए उम्मीदवारों के संबल

जगुरूक जनता नेटवर्क jagrukjanta.in.com



जयपुर। प्रदेश के 90 शहरी निकायों में अध्यक्ष पद पर नामांकन के अंतिम दिन 281 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। कुचेरा नगरपालिका में कांग्रेस और कुशलगढ़ में बीजेपी का अध्यक्ष निर्वाचन तय हो गया है। दोनों जगह केवल एक-एक नामांकन दाखिल हुआ है। अजमेर नगर निगम मेयर के लिए 5 उम्मीदवारों ने नामांकन किए हैं।

स्कूलों के लिए गाइडलाइन: सुबह साढ़े 10 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा कक्षा छटवीं से 8वीं तक के स्कूलों का समय, शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

जयपुर @ जगुरूक जनता। कोरोनाकाल में बंद हुए स्कूल अब धीरे-धीरे खुलने लगे हैं। राज्य सरकार ने बीते दिनों कक्षा छठवीं से आठवीं तक के छात्रों के लिए 8 फरवरी से स्कूल खोलने की अनुमति दी है। इस कड़ी में मंगलवार को शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने के संबंध में गाइडलाइन जारी की है। स्कूलों में छात्रों को सुबह साढ़े 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक पढ़ाने का समय निर्धारित किया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जारी गाइड लाइन के मुताबिक, स्कूल खोलने के एक दिन पहले 7 फरवरी को स्कूलों में परेंट्स-टीचर मीटिंग (पीटीएम) करना जरूरी होगा। इसमें अभिभावकों को स्कूल के लिए बनाई गई कोरोना

गाइडलाइन की जानकारी दी जाएगी। गाइडलाइन के मुताबिक कक्षा में सभी बच्चों को बुलाया जा सकेगा। स्कूल आने के लिए अभिभावक से सहमति लेना जरूरी होगा। आपको बता दें कि इससे पहले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए थे। स्कूल 18 जनवरी से खोले गए थे।

मोदी सरकार भारत को कॉर्पोरेट जगत के हाथों में बेच रही है-सैनी

जगुरूक जनता नेटवर्क jagrukjanta.net.com



चौमू। पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी ने मोदी सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश की संपत्ति उनको भी अपने पूंजीवादी दोस्तों को सौंपने की योजना बना ली है। इस बजट में मोदी सरकार ने एयरपोर्ट, सड़क, बिजली ट्रांसमिशन लाइन, रेलवे का डेडीक्रेटेड फ्रेट कॉरिडोर के हिस्से, वेयरहाउस, गैर, इंडियन ऑयल की पाइप लाइन और स्टेटिडियम को बेचेगी व सात बंदरगाह भी निजी हाथों में दिया जायगा। केंद्रीय बजट से स्पष्ट दिखाई देता है कि देश की आर्थिक स्थिति चिंताजनक है और भाजपा सरकार के पास ठोस दिशा नहीं है। बजट महंगाई बढ़ाने वाला है और इसमें किसानों, ब्रोकरगारों, लघु उद्योगों की स्थिति में सुधार के लिए कोई ब्यूटिंटी नहीं है साथ में पेडोल ड्रीज़ल के दाम बढ़ा दिए गए, इनकम टैक्स में कोई रात नहीं, कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दी गई, किसानों पर सह चार्ज लगा दिया। राजस्थान की पूरी तरह से उपेक्षा की गई। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना सहित लुम्बित रेल लाइनों और नए हाइवे की घोषणा न होना राज्य को जनता के साथ भेदभावपूर्ण है।

बढ़ती जा रही है। उक्त समस्या के समाधान हेतु निम्न उपाय किया जाना आवश्यक है क्रम संख्या 1 रोड पर बैरिकेट्स लगाए जाने क्रम संख्या दो वाहनों की गति को सीमित रखे जाने हेतु उपाय हो क्रम संख्या 3 रोड लाइट व ब्लीचिंग लाइट लगाई जावे क्रम संख्या 4 रोड संकेतक लगाए जावे। समस्या के समाधान हेतु जापन दिया गया जिला विधिक अधिकारियों से संपर्क कर सूचित किया जा चुका है। परंतु विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई नाही उक्त दुर्घटनाओं को रोके जाने हेतु कोई प्रभावी हाल ही नहीं निकाला गया उक्त दुर्घटनाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

सचिव एडवोकेट अजय कुमार शर्मा द्वारा जिनमें प्रदीप कुमार शर्मा ओम प्रकाश शर्मा विजय शर्मा मुकेश शर्मा कृष्णा शर्मा सीएल जिल्दल श्रवण लाल भगवान सहाय सांखला आदि अधिवक्ता एवं समाज बंधु मौजूद रहे।

ब्राह्मण समाज राजस्थान ने सड़क व परिवहन मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

जगुरूक जनता नेटवर्क jagrukjanta.net.com



चौमू। ब्राह्मण समाज राजस्थान जयपुर जिला देहात एडवोकेट अजय कुमार शर्मा (जिला विधि सचिव) द्वारा प्रताप सिंह खाचरियावास सड़क एवं परिवहन मंत्री राजस्थान सरकार के नाम उपखंड अधिकारी को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 जयपुर सीकर नेशनल हाईवे पर बनाए गए चौमू बायपास पर राधा स्वामी बाग भोज लावा कट हाइड्रो कट उदयपुरिया मोड़ गाँवदिगढ़ ताते डा मोड पर आए दिन वाहन दुर्घटना होती रहती है, इसके चलते अब तक संकड़ों से ज्यादा लोग अपनी जान गवा चुके हैं तथा कई परिवार उजड़ चुके हैं। इस संबंध में स्थानीय निवासियों द्वारा कई बार एनएच-एआई

के अधिकारियों से संपर्क कर सूचित किया जा चुका है। परंतु विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई नाही उक्त दुर्घटनाओं को रोके जाने हेतु कोई प्रभावी हाल ही नहीं निकाला गया उक्त दुर्घटनाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

100 वर्षीय रूपी देवी ने अपनी पूरी पेंशन 2 लाख 21 हजार की भेंट

जोधपुर @ जगुरूक जनता। चौपालसी हिलवाकिया बेरा प्रेम विहार की निवासी 100 वर्षीय रूपी देवी ने अपनी पूरी पेंशन 2 लाख 21 हजार रुपये भेंट की। चौखी पूर्व सरपंच गोविंद टाक ने बताया कि 100 वर्षीय रूपी देवी के 30 स्व. गोविंदराम ने अनूठी पहल पेश करते हुए अपनी पूरी पेंशन राशि भेंट की। उन्होंने परिवार के साथ राशि प्रदान की। जिसमें उन्होंने श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए 51000, भईदेईरिया गोशाला में 51000, फलाल गोशाला में 51000, वृद्ध आश्रम मंदिर में 51000 व रामबाग स्वर्गा आश्रम 21000 रुपये का अलग-अलग चेक प्रदान किए।

कांग्रेस-बीजेपी के प्रत्याशियों ने बाड़ंबंदी से निकल दाखिल किया नामांकन

हाड़ा की पत्नी हैं। सोमवार को केवल 19 उम्मीदवारों ने ही नामांकन भरे थे, ऐसे में शेष उम्मीदवारों ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। 90 निकायों में से 19 जगह कांग्रेस और 25 जगह बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है, बाकी जगह निर्दलियों के हाथ सत्ता की चाबी है। कांग्रेस 50 से ज्यादा निकायों में अपने अध्यक्ष बनाने का दावा कर रही है। जबकि भाजपा का दावा है कि वह बोर्ड की संख्या 45 तक ले जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी ने ज्यादातर निकायों में पार्षदों की बाड़ंबंदी कर रखी है। बाड़ंबंदी 8 फरवरी को उपाध्यक्ष के चुनाव तक चलेगी। अध्यक्ष के लिए 7 फरवरी को वोटिंग है। अध्यक्ष पद पर नामांकन की कल जांच होगी, 4 फरवरी तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 4 फरवरी को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा। अध्यक्ष पद पर 7 को पार्षद वोटिंग करेंगे और उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। उपाध्यक्ष के लिए 8 फरवरी को ही नामांकन, चुनाव और नतीजों की प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी होगी।

कांग्रेस और बीजेपी ने ज्यादातर निकायों में पार्षदों की बाड़ंबंदी कर रखी है। बाड़ंबंदी 8 फरवरी को उपाध्यक्ष के चुनाव तक चलेगी। अध्यक्ष के लिए 7 फरवरी को वोटिंग है। अध्यक्ष पद पर नामांकन की कल जांच होगी, 4 फरवरी तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 4 फरवरी को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा। अध्यक्ष पद पर 7 को पार्षद वोटिंग करेंगे और उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। उपाध्यक्ष के लिए 8 फरवरी को ही नामांकन, चुनाव और नतीजों की प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी होगी।

वैक्सीनेशन का दूसरा फेज कल से बीएसएफ, सीआईएसएफ, पुलिस समेत अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा टीका

जगुरूक जनता नेटवर्क jagrukjanta.net.com

जयपुर। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण 4 फरवरी से शुरू हो रहा है। दूसरे चरण में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अलावा राजस्व विभाग, स्थानीय निकाय, पंचायतीराज विभाग और पुलिस कार्मिकों को टीका लगाया जाएगा। इसको लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस फेज में 2.39 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स का डेटा तैयार कर लिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन पहले फेज में 3 लाख 39 हजार 218 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। हेल्थ वर्कर्स को अब भी वैक्सीन लगाने का काम जारी है। वहीं, विभाग ने अब दूसरे फेज की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स का डेटा भी कोविड एप पर अपलोड करना शुरू कर दिया है। अब तक राजस्व विभाग के 22 हजार 520, स्थानीय निकायों के 55 हजार 362 और पुलिस व सैन्य बलों के 1 लाख 61 हजार 236 लोगों का पंजीकरण हो चुका है। इस तरह कुल 2 लाख 39 हजार 118 लोगों को दूसरे चरण में टीका लगाया जाएगा।

सेंट्रल बजट से व्यापारी नाखुश-फोर्टी

जगुरूक जनता नेटवर्क jagrukjanta.net.com

फोर्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने बताया कि इनकमटैक्स में व्यापारियों को सरकार से राहत की बहुत ज्यादा उम्मीद थी परन्तु इसके स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिससे व्यापारियों को निराशा हाथ लगी है। फोर्टी उपाध्यक्ष जगदीश सोमानी ने बताया वर्तमान में महंगाई निरंतर बढ़ रही है परन्तु सरकार ने लोहा इस्पात व कॉपर पर ड्यूटी कम की जिससे निश्चित रूप से उद्योगों को राहत मिलेगी साथ ही 2 हिस्सों में इकोनॉमिक कोरीडोर जोन बनाने व न्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा भी सरकार का स्वागत योग्य कदम है। इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। फोर्टी चीफ सेक्रेटरी गिर्धारीलाल खण्डेलवाल ने बताया सरकार द्वारा कुछ चीजों में रियायत दी गई है जिसमें ग्रामीण उद्योग के लिये जो आबल बकिल किये हैं वो काफी सराहनीय कदम है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट अतिरिक्त एक साल बढ़ी, स्टार्टअप के लिए टैक्स हॉलिडे का दावा करके लिए 31 मार्च 2022 तक तक का वाक देना व कस्टम ड्यूटी के मामले में 400 पुरानी छूटों का रिवां किया जाएगा। 1 अक्टूबर से नए कस्टम ड्यूटी स्ट्रुक्चर को लागू किए जाने की कोशिश करना महत्वपूर्ण है।



सरती संगम फैडरेशन की 4321 महिलाओं को मिला कुशल नेतृत्व

महिलाएं अपने परिजनों को सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत करें- पुलिस अधीक्षक, दीपक भार्गव



जगुरूक जनता नेटवर्क jagrukjanta.net.com

चिन्नोडुगाढ़। हिन्दुस्तान जिकें एवं मंजरी फाउण्डेशन के संयुक्त तत्वाधान में सखी संगम फेडरेशन की वार्षिक आमसभा का आयोजन सखी कार्यालय परिसर चिन्नोडुगाढ़ में आयोजित किया गया। हिन्दुस्तान जिकें के आस पास के 47 गांवों की 150 स्थानीय महिलाओं ने निर्विरोध सखी अंजु सालवी, अनिशा बानू और सुनाय कुमावत को अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में चुना। अध्यक्ष अंजु सालवी ने सखी संगम फेडरेशन की वार्षिक उपलब्धियों को कार्यक्रम में साझा किया। समाजोह के मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलायी। उन्होंने महिलाओं के सशक्त संगठन सखी संगम फेडरेशन के रूप में जुड़ने के लिए बधाई देते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बने हुए हैं जिसको मंजूर रखते हुए अलग से महिला थाने की व्यवस्था भी की गयी है। परिवार के सभी सदस्यों को सड़क सुरक्षा प्रति सचेत करने के लिए घर की महिला का मुख्य योगदान होता है। उन्होंने आह्वान किया कि महिलाएं सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध करें। कार्यक्रम में केंनरा बैंक के जिला क्षेत्रीय प्रबंधक ओमप्रकाश, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आजोलिया का खेडा के प्रेमकुमार एवं भूमि विकास बैंक के चेयरमैन कमलेश पुरोहित शामिल हुए। जिन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अल्पबचत की प्राथमिकता और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर अपने संपूर्ण आर्थिक उन्नयन पर विस्तार से चर्चा की। पुरुषों में प्रचलित मद्यपान

जैसी कुरीति पर महिलाओं के नेतृत्व का सामुहिक आह्वान किया। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा श्रीमती कल्याणी दीक्षित ने सभी महिलाओं को घर की रानी के रूप में संबोधित करते हुए फेडरेशन बनने की उनकी यात्रा के लिए बधाई दी। सभी अतिथियों ने सखी महिलाओं के उत्पादों मसालें, हेण्डमेड बैग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि हिन्दुस्तान जिकें के सीएसआर कार्यक्रम में संचालित सखी परियोजना में जिले के गंगार, चिन्नोडुगाढ़ और भंडेर पंचायत समिति के चिन्हित 47 गांवों की 4321 ग्रामीण महिलाएं सखी कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। समाजिक सुरक्षा योजना, उज्वला योजना, मनरागा जैसी सरकारी योजनाओं में

सखी महिलाएं लाभान्वित होकर अपने परिवार को संबल प्रदान कर रही हैं। अपनी छोटी छोटी बचत से स्वयं सहायता समूह का गठन कर 3.4 ग्राम संगठनों को एकिकृत कर सखी संगम फेडरेशन के रूप में अपना संगठन बना चुकी हैं जिससे अब तक उन्होंने महिलाओं को 2 करोड़ 32 लाख की त्रधा राशि मुहैया कराया है। हिन्दुस्तान जिकें द्वारा सिलाई उत्पादन, मसाला उत्पादन, मोमबत्ती उत्पादन केंद्र जैसे स्वरोजगार उन्मुख योजनाओं से सखी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को निरंतर गति मिल रही है। गौरतलब है कि कोविड 19 के चुनौतिपूर्ण दौर में सखी महिलाओं ने 92 हजार मारक बनाकर संपूर्ण जिलें में कोविड के प्रति जागरूक किया। 22 दिनों तक दैनिक मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों को भी और ताजा भोजन बना उपलब्ध करा सहायता की। जरूरतमंद परिवारों के लिए घर घर जा कर कई किटल अनाज एकत्रित किया। आम सभा में हिन्दुस्तान जिकें की सीएसआर टीम के विशाल अग्रवाल, अरुणा चोटा, स्वतलाना साहु, मयंक दर्जी, मंजरी फाउण्डेशन से शिवओम, प्रभु सालवी, अमरीश त्यागी, हेरंदे शर्मा, नागेन्द्र गिरी गोस्वामी ने अपनी सक्रीय भागीदारी निभायी।

पल्लस पोलिया में अभियान में बच्चों की गटकी जिंदगी की दो बूंद



जयपुर @ जागरूक जनता। पीपीपी मोड पर विकल्प ड्रिडिया सोसाइटी द्वारा संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अम्बाबाडी वार्ड 10 द्वारा क्षेत्र की 41000 की जनसंख्या हेतु पल्लस पोलिया कार्यक्रम का आगाज किया गया।

अविनाश सुर और स्वर सम्मान से सम्मानित

जयपुर @ जागरूक जनता। अपनी प्रतिभा से बॉलीवुड में ख्यास मक़ाम बनाने वाले जयपुर के प्रसिद्ध कवि और गीतकार अविनाश रिपार्टी को जयपुर में 'सुर और स्वर' सम्मान से नवाजा गया।

श्री श्याम महोत्सव सेवा समिति ने किया रक्तदान शिविर आयोजित



जयपुर @ जागरूक जनता। श्री श्याम महोत्सव सेवा समिति की ओर से मंगलवार को निवारु रोड के पास नांगल जैसा बोहरा सर्वेक्षक भवन में 14वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया।

कोरोना जन आंदोलन के तहत निकाली रैली

पीपाइशहर @ जागरूक जनता। सरकार द्वारा कोरोना जनआंदोलन के तहत नगर पालिका पीपाइशहर में मास्क वितरण किए गए।

बालिका शिक्षा का प्रसार करे-पल्लवी कुलहरी



पीपाइशहर @ जागरूक जनता। पीपाइशहर उपखंड मुख्यालय की ग्राम पंचायत रामझावास कला मे मंगलवार को महिला एवं अधिकारिता विभाग की सुपरवाइजर पल्लवी कुलहरी ने सास बहू सम्मेलन का आयोजन किया गया।

प्रथम प्रयास में ही आदित्य बने सीए

कोटपूतली @ जागरूक जनता। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम सुदरपुरा दादा निवासी 22 वर्षीय छात्र आदित्य पुत्र संजय मिश्रल ने टा इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित नवंबर 2020 की परीक्षा परिणामों में प्रथम प्रयास में ही सफलता अर्जित की है।

समाज को आगे आकर सभी को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं-गर्ग

जागरूक जनता नेटवर्क jagrukjanta.net/com

भुसावर। शिक्षा के लिए हमें सभी का सहयोग करना चाहिए सभी समाज के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना होगा, अग्रवाल समाज अग्रज रहा है, इस भवन में अगर एक ऐसा पुस्तकालय बना दिया जाए जिसमें क्षेत्र के सभी वर्ग के सभी जाति के सभी धर्म के बच्चे अध्ययन कर अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें इससे बड़ी समाज भवन दानदाता एवं उन सहित समस्त एकसी विचारधारा वाले व्यक्तियों कि रहेगी।



भुसावर स्थित पैतृक भवन को अग्रवाल समाज के लिए दान एवं पवन लोकार्पण के अवसर पर अपना उद्घोष दे रहे थे। कार्यक्रम को पंजाब हरियाणा सरकार के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यशपाल गर्ग, सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया।

आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती यह एक वहसीपन है-डॉ शर्मा



यतेंद्र पाण्डेय @ जागरूक जनता jagrukjanta.net/com भूतल पर। मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वह कब किस प्रकार किसी प्रलोभन से या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के वशीभूत किसी को भी कितना ही नुकसान पहुंचा सकता है उसे यह आवास नहीं रहता की मैं जो कर रहा हूँ उससे कितने लोगों को हर्नी होगा देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसे ही एक व्यक्ति द्वारा परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आजादी मिलने के कुछ ही माह बाद गोलियों का निशाना बनाकर देश को देश में आतंक फैलाने का प्रयास किया यह कहना है शहीद सुशील कुमार शर्मा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा का शर्मा राजस्थान के भरतपुर जिले में भुसावर स्थित फाउंडेशन के राजस्थान इकाई कार्यालय पर अपना उद्घोष दे रहे थे शर्मा ने कहा की वर्तमान आतंकवाद एवं आज से 50 वर्ष पूर्व के आतंकवाद ने सभी का साफा माला एवं प्रतीक परिस्थितियों दूसरे प्रकार की थी देश

जागरूक जनता jagrukjanta.net फेसबुक पेज अपडेट आगे बढ़े

ANCHOR मूर्ति अनावरण

आपसी भाईचारे के साथ एकजुटता से विकास के पथ पर अग्रसर होने पर ही अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि - राज्यमंत्री यादव

शहीद शैलेन्द्र कुमार मीणा के नाम से होगा राजकीय विद्यालय का नामकरण

राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव, पूर्व केन्द्रिय मंत्री नमोनारायण मीणा, थानागाजी विधायक कांतिलाल मीणा सहित अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम में लिया भाग

जागरूक जनता नेटवर्क jagrukjanta.net/com कोटपूतली। कस्बे के निकटवर्ती खड्ड गाँव में शहीद शैलेन्द्र कुमार मीणा का मूर्ति अनावरण कार्यक्रम आयोजित हुआ।

अखिल भारतीय गुर्जर महासम्मेलन आयोजित प्रतिभाओं को मिला राष्ट्रीय गुर्जर गौरव अवॉर्ड

जागरूक जनता नेटवर्क jagrukjanta.net/com

जयपुर/कोटपूतली। अखिल भारतीय गुर्जर महासंघ के तत्वावधान में गुलाबी नगरी जयपुर में अखिल भारतीय गुर्जर महासम्मेलन एवं गुर्जर गौरव सम्मान समारोह का आयोजन हुआ।

उपखण्ड अधिकारी सुनीता मीणा ने किया औचक निरीक्षण



जागरूक जनता नेटवर्क jagrukjanta.net/com कोटपूतली। एसडीएम सुनीता मीणा ने पावटा में औचक निरीक्षण किया।

गठन व राजनैतिक हिस्सेदारी पर चर्चा की। इस दौरान समाजसेवी दामोदर गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष रामचन्द्र धाबाई ने भी विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर मुनेश गुर्जर ने की।

स्वर्गीय इन्द्र सिंह भाटी की पुण्यतिथि पर दौड़ प्रतियोगिता आयोजित



कोटपूतली। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम दांतिल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में स्वर्गीय इन्द्र सिंह भाटी की पुण्यतिथि पर भाटी परिवार की ओर से 100,400 एवं 1600 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

मीणा, पूर्व विधायक घनश्याम मेहर,पीसीसी मेम्बर जगदीश मीणा ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

जागरूक जनता नेटवर्क jagrukjanta.net/com मीणा, पूर्व विधायक घनश्याम मेहर,पीसीसी मेम्बर जगदीश मीणा ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

राज्यमंत्री यादव ने शहीद शैलेन्द्र कुमार मीणा के नाम पर खड्ड गांव के राजकीय विद्यालय का नामकरण किये जाने की घोषणा की है।

बीएसएफ में तैनात थे शहीद शैलेन्द्र

शहीद शैलेन्द्र मीणा बीएसएफ की 60 वीं बटालियन में तैनात थे। जो कि 18 जनवरी को ड्यूटी के दौरान मिजोरम में शहीद हो गये थे।

Smaller EMIs on 30 YEAR HOME LOANS

8.45%*

Interest Rate

housing mortgage loan also available



अब अपनी पुरानी गाड़ी पर

तक लोन करवायें...

कीमत का 150%



authorised channel partner

Aarna associate

Call us : 9828333666